बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 115

रणनीतिक अवसर

सरकारी स्वामित्व वाले मझगांव डॉक्स लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा 5.3 करोड़ डॉलर के सौदे के तहत कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी (सीडीपीएलसी) में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के मजबूत होते समुद्री प्रभाव के रूप में देखा जाना चाहिए। भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोत और पनडुब्बियां तथा तेल उत्खनन के लिए प्लेटफॉर्म और पोत बनाने वाली एमडीएल देश की सबसे बड़ी रक्षा शिपयार्ड और एक नवरत्न कंपनी है। घाटे में चल रही और श्रीलंका की सबसे बड़ी पोत निर्माता और मरम्मत इकाई सीडीपीएलसी का प्रस्तावित अधिग्रहण एमडीएल के पोर्टफोलियो में अहम विस्तार करेगा। इसके अतिरिक्त इसका शिपयार्ड गहरे पानी में स्थित कोलंबो बंदरगाह के करीब है जो माल के आवागमन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। एक सरकारी कंपनी के रूप में यह सौदा श्रीलंका में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाला है। ध्यान रहे कि चीन ने पहले ही श्रीलंका में काफी दखल कर लिया है। हंबनटोटा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह समूह में पहले ही चीन की 85 फीसदी हिस्सेदारी है और उसने श्रीलंका के दक्षिण में स्थित बंदरगाह को 99 वर्ष की लीज पर लिया है।

एमडीएल और सीडीपीसीएल के बीच हुआ रणनीतिक सौदा भारत और श्रीलंका के अधिकारियों के बीच गहन चर्चा का परिणाम है। यह सौदा किसी निजी कंपनी के बजाय देश की एक प्रमुख सरकारी कंपनी के साथ हुआ और इसे भी एक अहम संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। यह बताता है कि गत वर्ष सितंबर में हुए चुनाव में अनुरा दिशानायके के जीतने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट बढ़ी है। अपनी चीन समर्थक छवि से जुड़े अनुमानों के विपरीत दिशानायके ने श्रीलंका को सबसे अधिक कर्ज देने वाले चीन और भारत के बीच एक संतुलन कायम करने का प्रयास किया है। ध्यान रहे कि मुश्किल समय में भारत ने उसे आपात ऋण देने का बंदोबस्त किया था। भारत वह पहला देश था जहां दिशानायके राष्ट्रपति बनने के बाद विदेश यात्रा पर आए।

सीडीपीएलसी गत वर्ष नवंबर से ही मुश्किलों से जूझ रही है जब उसकी जापानी साझेदार ओनोमिची डॉकयार्ड कंपनी (51 फीसदी की हिस्सेदार) उस समय बाहर निकल गई जब श्रीलंका और जापान के बीच वित्तीय राहत संबंधी बातचीत विफल हो गई। कंपनी डिफॉल्ट का सामना कर रही थी और वहां छंटनी और बंदी के बादल मंडरा रहे थे जब संभावित खरीदार के रूप में कुछ अन्य कंपनियों के साथ एमडीएल का चयन किया गया। यह सौदा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक नजर आता है। सीडीपीएलसी के पास करीब 30 करोड़ डॉलर के ऑर्डर हैं और एमडीएल की तकनीक और भारतीय आपूर्ति श्रृंखला और बाजार उसके लिए अवसर लेकर आए हैं। एमडीएल भारतीय नौसेना के लिए तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियां और छह डीजल-बिजली चालित स्टेल्थ पनडुब्बियां बना रही है। सीडीपीएलसी का अधिग्रहण भारतीय कंपनी को विस्तार का अवसर देगा ताकि वह केवल भारतीय नौसेना के ऑर्डर पर निर्भर न रहे और पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका के उन देशों के साथ कारोबार कर सके जहां श्रीलंकाई कंपनी का बाजार है।

उस लिहाज से देखें तो यह सौद भारतीय सरकारी कंपनी के लिए एक परीक्षा की तरह होगा कि वह विदेशी कारोबार को किस तरह संभाल पाती है। विदेशी कारोबारों में सरकारी कंपनियों का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। ओएनजीसी विदेश और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के साथ ऊर्जा क्षेत्र में हम विदेश में काम कर रहे हैं। रेल इंडियन टेक्निकल ऐंड इकनॉमिक सर्विस यानी राइट्स और डब्ल्यूएपीसीओएस (जल क्षेत्र की मशविरा फर्म) जैसी कंपनियां भी अंतरराष्ट्रीय मशविरा कार्यक्रमों में प्रतिस्पर्धी साबित हुई हैं। परंतु कई अन्य को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है जिसने देश के सरकारी क्षेत्र की राह मुश्किल की है। इन दिक्कतों में लालफीताशाही और तकनीकी ठहराव की भी भूमिका रही है। एमडीएल में ये कमियां नहीं हैं और वह किफायती प्रबंधन के लिए जानी जाती है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां चीन के सरकारी उपक्रमों का दबदबा है वहां काफी कुछ इसकी कामयाबी पर भी निर्भर करेगा।

विनय सिन्हा

डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता और बहुपक्षीय समझौते

बहुपक्षीय समझौते विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के भविष्य के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बता रही हैं अमिता बत्रा

इस महीने के आरंभ में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो-इवेला ने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में अपने भाषण में जोर देकर कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों के पक्ष में बोलने की आवश्यकता है। खासतौर पर तब जबकि दबदबे वाली फंडिंग अर्थव्यवस्था ने इसकी आवाज और प्रासंगिकता को दबाने की ठानी है। उनका वक्तव्य डब्ल्यूटीओ के लिए सुखद है। अपनी बुनियादी प्रक्रियाओं और मुक्त व्यापार को आगे बढ़ाने के लक्ष्य की बात करें तो यह संस्थान इस समय एक चौराहे पर है। अमेरिका द्वारा विवाद निस्तारण प्रणाली की अपीलीय संस्था में नियुक्तियों को अवरुद्ध किए जाने को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है लेकिन दीर्घकालिक वार्ताओं और परिणामों की कमी की बात करें तो संस्था लंबे समय से मुश्किलों से गुजर रही है।

यह बात तो सभी जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ की सदस्यता का विस्तार किया गया और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऐंड ट्रेड (गैट) के 23 संस्थापक देशों से 1994 में इसके डब्ल्यूटीओ में परिवर्तित होने पर इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 128 हो गई। 2024 में यह संख्या 166 हो गई। परंतु इस दौरान चुनौतियां भी आईं। कृषि सब्सिडी, गैर कृषि बाजार पहुंच और सेवा उदारीकरण जैसे अहम मुद्दों का सहमति आधारित हल पाना मुश्किल बना रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों के अलग-अलग हित जुड़े हुए थे। व्यापार सुविधा समझौते और अभी हाल ही में मत्स्यपालन से जुड़ी सब्सिडी के बारे में भी काफी लंबी और कठिन चर्चा के बाद सहमति बन सकी। इन्हें लेकर दशक भर से लंबी वार्ताएं चलीं। डब्ल्यूटीओ के अहम मुद्दों पर लंबे समय से विवादों और गतिरोध के कारण इसके इकलौते व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम यानी दोहा विकास दौर को वास्तव में निलंबित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश मंत्रीस्तरीय बैठकें केवल पहले किए गए समझौतों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रशासनिक निर्णयों तक सिमट गई हैं। इसलिए डब्ल्यूटीओ के नियम और प्रावधान सीमित हुए हैं।

बहरहाल, वैश्विक व्यापार अब बहुत हद तक वैश्विक मूल्य श्रृंखला यानी जीवीसी से संचालित होता है और उसने मुक्त व्यापार समझौतों यानी एफटीए और मुद्दा आधारित बहुपक्षीय समझौतों को नियम निर्माण का वैकल्पिक मार्ग बनाया है। गैट के अनुच्छेद 24 के तहत होने वाले एफटीए और दो या अधिक सदस्य देशों के बीच व्यापार उदारीकरण का 21वीं सदी में काफी विस्तार देखने को मिला है। सन 2000 में जहां डब्ल्यूटीओ की जानकारी में 100 से भी कम एफटीए थे वहीं 2025 में इनकी तादाद 600 पार कर चुकी है।

इनकी तादाद बढ़ने के साथ ही एफटीए में गहराई भी आई है। इनमें से अधिकांश में बौद्धिक संपदा, निवेश और सेवा उदारीकरण के साथ पर्यावरण और टिकाऊ शासन को लेकर काफी अहम मुद्दे शामिल होते हैं। एक समय सदस्यता के अतिक्रमण और विभिन्न एफटीए में स्रोत नियम की जटिलता के कारण बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की आलोचना की जाती थी लेकिन उन्होंने भी सदस्य देशों के लिए एफटीए को सहज बनाने में अहम भूमिका निभाई है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से कई को एफटीए में भागीदारी से लाभ हुआ है।

डब्ल्यूटीओ के अधीन बहुपक्षीय समझौतों में भी प्रगति हुई है हालांकि यह प्रगति एफटीए की तुलना में बहुत धीमी रही है। डब्ल्यूटीओ के अधीन पहला बहुपक्षीय समझौता 1996 में हुआ सूचना प्रौद्योगिकी समझौता था। वहां प्रतिभागी देशों ने चिह्नित सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी। हाल के समय में नए दौर के नीतिगत क्षेत्रों मसलन ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा और वैकल्पिक अंतरिम विवाद निस्तारण प्रक्रिया आदि में बहुपक्षीय समझौतों के तहत पहल की गई है लेकिन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी और निर्णायक बातचीत को अंजाम देना कठिन है।

वास्तव में बहुपक्षीय समझौते विवादास्पद रहे हैं क्योंकि कई बार इनमें रुचि रखने वाले सदस्य देश किसी ऐसे मुद्दे पर बातचीत शुरू कर देते हैं जिसे संपूर्ण डब्ल्यूटीओ की सदस्यता का प्रतिनिधि नहीं माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप इन समझौतो में एजेंडा आगे बढ़ाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है और जो पहलकदमी करता है उसे ही लाभ हासिल होने की संभावना अधिक रहती है। इससे न केवल बातचीत का सहमति आधारित रुख सीमित होता है जो डब्ल्यूटीओ का अनिवार्य हिस्सा है बल्कि यह उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद के विकासशील देशों के लंबे संघर्ष को नकारता है जिसके तहत उन्होंने गैर कारोबारी मुद्दों को दूर रखते हुए दोहा दौर के एजेंडे को आगे बढ़ाया। बहरहाल तब से अब तक विश्व व्यापार में बहुत कुछ बदल चुका है।

पहली बात, 21वीं सदी की जीवीसी आधारित विश्व व्यापार व्यवस्था के अंतर्निहित तंत्र को वस्तुओं, निवेश और सेवा व्यापार के उदारीकरण के बीच एक अटूट संबंध के रूप में समझने की आवश्यकता है। इनमें से हर क्षेत्र में नियमों और नियामकीय ढांचे का समुचित सेट जरूरी है ताकि विश्व व्यापार को सुविधा मिले। दूसरी बात, भारत समेत कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने जिसे 'गैर व्यापार' श्रेणी में सूचीबद्ध किया है और बहुपक्षीय समझौतों में जिनका प्रतिरोध हो रहा है वे पहले ही मुक्त व्यापार समझौते के दायरे में हैं। उदाहरण के लिए जबकि निवेश सुविधा पर बहुपक्षीय बातचीत को डब्ल्यूटीओ के कुछ सदस्य चुनौती दे रहे हैं, वहीं 21वीं सदी के अधिकांश एफटीए में निवेश चैप्टर में, निवेश सुविधा से आगे बढ़कर निवेश संरक्षण, निवेशक और राज्य के बीच विवादों का समाधान और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर गहरे प्रावधान शामिल हैं। इसी प्रकार ईएसजी से संबंधित प्रावधान जिनमें से कई को लंबे समय से गैर-व्यापार मुद्दा माना जाता है, उनमें 2010 के दशक के एफटीए में काफी इजाफा देखा गया। तीसरी बात, जहां बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं जोर नहीं पकड़ पातीं या लंबित रह जाती हैं, वहां संबंधित देशों ने क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर डब्ल्यूटीओ के बाहर द्विपक्षीय समझौतों का विकल्प चुना। उदाहरण के लिए अमेरिका-जापान और ऑस्ट्रेलिया-सिंगापुर ने 2020 में द्विपक्षीय डिजिटल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया ने मार्च 2025 में एक डिजिटल व्यापार समझौता किया। चौथी बात, हम एक ऐसे युग में हैं जहां संरक्षणवादी एकपक्षीयता और नीतिगत अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। ऐसे में वैश्विक व्यापार नियमों में निरंतरता पर विचार करना होगा।

हमें वैकल्पिक प्रणालियां अपनानी होंगी। इसके साथ ही, विश्व व्यापार संगठन में नियमों के रूप में पीए-वार्ता के परिणामों को शामिल करने में वैधता के मुद्दों से निपटने का प्रयास किया जाना चाहिए। डब्ल्यूटीओ को हाशिए पर जाने से बचाने के लिए, केवल पुराने समझौतों पर नियमित प्रशासनिक उपाय करने तक सीमित रहने से रोकने के लिए, और तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक व्यापार संदर्भ की जरूरतों के अनुरूप इसके विकास में सहायता करने के लिए वैकल्पिक साधनों यानी एफटीए और बहुपक्षीय समझौतों के संयोजन की आवश्यकता है।

(लेखिका जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र में प्राध्यापक हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

भारतीय स्टेट बैंक के बेमिसाल 70 साल

देश का सबसे बड़ा कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 1 जुलाई को अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। एसबीआई को इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं! भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ और परिसंपत्ति के आधार पर दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल एकमात्र भारतीय बैंक एसबीआई देश के हर तीन व्यक्तियों में एक के लिए बैंकिंग गतिविधियों का ठिकाना है।

वित्त वर्ष 2024-25 में एसबीआई का शुद्ध मुनाफा 77,561 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आय के लिहाज से भी यह शीर्ष 100 वैश्विक कंपनियों में शुमार रहा है। इस सूची में ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली यह तीसरी भारतीय इकाई है। आइए, 1955 से 2025 तक की एसबीआई की यात्रा पर नजर डालते हैं।

एसबीआई को पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 30 जून, 1955 को (इम्पीरियल बैंक का आखिरी दिन) इसके पास 210.94 करोड़ रुपये जमा (डिपॉजिट) और 116.24 करोड़ रुपये ऋण का बहीखाता था। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10,977 करोड़ रुपये था। मार्च 2025 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3,000 गुना बढ़कर 330.68 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुका है। इस अवधि के दौरान एसबीआई की जमा रकम 25,000 गुना बढ़कर 53.82 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुकी है। बैंक की ऋण बही का आकार भी 35,800 गुना बढ़ कर 41.63 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

पिछले 70 वर्षों के दौरान बैंक की आय 8.50 करोड़ रुपये से बढ़ कर 5.24 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है। मुनाफा भी 1.36 करोड़ रुपये से बढ़कर 70,901 करोड़ रुपये हो चुका है। एसबीआई ने 1955 में 90 लाख रुपये लाभांश दिया था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 14,190 करोड़ रुपये हो चुका है। इस दौरान कर्मचारियों की संख्या भी 14,388 से बढ़कर 2,36,226 हो गई है। बैंक का प्रति कर्मचारी मुनाफा 90,000 रुपये से बढ़कर 29,91,000 रुपये हो गया है और इसकी शाखाओं की संख्या 496 से बढ़कर 22,397 हो गई है।

श्रीनगर की डल झील में तैरते एटीएम से लेकर केरल के एर्णाकुलम और वाइपिन में जेटी तक एसबीआई के एटीएम तैनात हैं। विदेश में इसके कार्यालयों की संख्या 8 से बढ़कर 244 तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी म्युचुअल फंड कंपनी भी एसबीआई के नाम है और क्रेडिट कार्ड कारोबार में यह दूसरे स्थान पर है। इसकी जीवन बीमा इकाई निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में एक है। एसबीआई की 18 सहायक इकाइयों में से दो सूचीबद्ध हैं। करीब 6,200 करोड़ रुपये निवेश वाली इसकी सहायक इकाइयों का मौजूदा मूल्यांकन 3.5 लाख करोड़ रुपये है।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

देश में कुल बैंक जमा में एसबीआई की हिस्सेदारी 22.5 फीसदी है और ऋण आवंटन में यह 19.5फीसदी है। खुदरा ऋण, आवास ऋण आदि कारोबारी खंडों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी 20 से 30फीसदी के बीच है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) में एसबीआई की हिस्सेदारी लगभग 30 फीसदी है।

एसबीआई को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधि कहना अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि यह अपनी भूमिका पूरी मजबूती और मुस्तैदी से निभा रहा है। वर्ष 1992 में भुगतान संकट के दौरान एसबीआई ने इंडिया डेवलपमेंट बॉन्ड के माध्यम से 1.6 अरब डॉलर जुटाए थे। एसबीआई ने 1998 में फिर इसे दोहराया। पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे तब एसबीआई ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड के जरिये 4.3 अरब डॉलर जुटाए थे।

एसबीआई के नाम कई ऐसी उपलब्धियां दर्ज हैं। उदाहरण के लिए 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान एसबीआई ने रक्षा क्षेत्र के लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए कई विशेष ऋण योजनाएं शुरू कीं। देश में मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन शुरू (1973 में) करने वाला एसबीआई पहला बैंक है। म्युचुअल फंड क्षेत्र के उदारीकरण के बाद इसने म्युचुअल फंड कंपनी की भी स्थापना की। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) के बाद यह पहली म्युचुअल फंड कंपनी थी।

एसबीआई की 70 वर्ष की यात्रा की सबसे खास बात यह रही है कि यह समय के साथ अपने कारोबारी तौर-तरीके बदलता रहा है। इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म 'योनो' इस बात की मिसाल है। साल 2017 में शुरू हुआ 'योनो' एसबीआई के ग्राहकों के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस है। बैंक के 90 फीसदी से अधिक लेनदेन न केवल 'योनो' से हो रहे हैं बल्कि नए कारोबारों में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी है और इससे दूसरी इकाइयों के उत्पाद एवं फीस आधारित योजनाएं भी बेची जा रही हैं।

वित्त वर्ष 2018 से 2024 के बीच एसबीआई ने अपना बहीखाता दोगुना कर लिया। यह कारनामा करना निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी मुश्किल है। कुछ कारोबारी खंडों में देर से उतरने के बावजूद यह अच्छी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में कामयाब रहा है। देश में खुदरा ऋण कारोबार में 15.06 लाख करोड़ रुपये के बहीखाते के साथ एसबीआई की 25 फीसदी हिस्सेदारी है। आवास ऋण खंड के साथ भी यही बात लागू होती है। यह 8.3 लाख करोड़ रुपये की आवास ऋण के साथ एचडीएफसी बैंक को टक्कर दे रहा है।

किसी बैंक के सुदृढ़ संचालन में इसके कर्मचारियों की भूमिका सबसे अहम होती है। एसबीआई इस मोर्चे पर भी बाजी मार लेता है। 1994 में बैंकिंग कारोबार निजी क्षेत्रों के लिए खुलने के बाद कई निजी बैंक अस्तित्व में आए। उनमें ज्यादातर की कमान उस समय एसबीआई से गए लोगों ने संभाली थी। इस समय कम से कम पांच निजी बैंकों के संचालन की कमान एसबीआई के पूर्व बैंकरों के हाथों में है।

हां, कुछ खंड ऐसे भी हैं जहां पर एसबीआई को कमर कसने की जरूरत है। चालू खाते की संख्या बढ़ाना ऐसा ही एक क्षेत्र है। सरकारी रकम की आमद तेजी से कम होने के बाद एसबीआई को पूंजी पर लागत कम करने के लिए कंपनियों से शून्य लागत वाले चालू खाते हासिल करने की जरूरत है। एसबीआई को लागत-आय का अनुपात भी सुधारना होगा जो इस समय बड़े निजी बैंकों से अधिक है।

एसबीआई देश में समाज में ऊपर से नीचे सभी तबके की जरूरत का ख्याल रख रहा है। एसबीआई ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 21 राज्यों में कम से कम 2,200 मोचियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक ऋण दिए हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र में हज्जामों को भी लघु ऋण उपलब्ध करा रहा है।

एसबीआई को पिछले दशक में कई बड़े ऋणों पर नुकसान झेलना पड़ा है मगर अब इसकी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) कम होकर ऋण बहीखाते का मात्र 0.47 फीसदी रह गई हैं। उम्मीद करता हूं कि इस मोर्चे पर आगे भी इसकी सेहत मजबूत बनी रहेगी। एसबीआई की स्थापना दिवस पर यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक के वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

परमाणु ऊर्जा का होगा सकारात्मक उपयोग

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए 'परमाणु ऊर्जा मिशन' की शुरुआत की गई है। सरकार ने इस साल के आम बजट में वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8,000 मेगावॉट से बढ़ाकर एक लाख मेगावॉट करने का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा मिशन का उद्देश्य लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत वर्ष 2033 तक कम-से-कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों को चालू किया जाएगा। मिशन के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 एवं परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा क्षमता एवं वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करना है, लेकिन फिलहाल भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लगभग 75 फीसदी के लिए कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर है। इसलिए यह मिशन परमाणु ऊर्जा को एक महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप मे स्थापित करने के लिए अहम साबित होगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व एवं संचालन भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम के पास है। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्यों और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन संरचनात्मक विनियामक चुनौतियां बनी हुई हैं। पुरानी नीतियों में संशोधन करके, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देकर, स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाकर तथा विनियामक ढांचे को सुव्यवस्थित कर इस क्षेत्र को पुनर्जीवित और सक्षम किया जा सकता है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास, मप्र

सरकार ने बजट में वर्ष 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8,000 मेगावॉट से बढ़ाकर एक लाख मेगावॉट करने का लक्ष्य रखा है

सालाना फास्टैग पास है हितकारी

सालाना फास्टैग निश्चित तौर पर कारगर साबित होगा। समय की बचत एवं आवागमन की सुगमता रहेगी। नियमित आवाजाही वाले वाहन चालक एक बार 3,000 रुपये का पास खरीदकर देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर साल में 200 बार सफर कर सकते हैं। इससे उन्हें बार-बार फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सालाना पास नीति से वाहन चालकों एवं सरकार दोनों को लाभ ही लाभ है। वाहन चालकों को समय के साथ पैसे की बचत होगी।

प्रदीप गौतम सुमन, रीवा, मप्र

सालाना फास्टैग से सहूलियत

इस साल 15 अगस्त से शुरू होने वाले फास्टैग के सालाना पास से राष्ट्रीय राजमार्गों पर हमेशा यात्रा करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। हालांकि, ट्रांसपोर्ट संघों की मांग है कि इसमें वाणिज्यिक वाहनों को भी शामिल किया जाए मगर सरकार शायद अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। साल में 200 यात्राओं पर टोल टैक्स नहीं देने से आम लोगों की जेब पर बोझ कम होगा।

रोशन कुशवाहा, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), बरेली के 11वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं। इस दौरान मुर्मू ने कहा कि 'पशु' शब्द का इस्तेमाल करना 'ठीक नहीं है' और उन्होंने जानवरों को 'जीवन धन' करार दिया। मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे।

भारतीय संविधान

विविधता में एकता

भारतीय संविधान ऐसा नियम है जो भारत की विविधता को एक राष्ट्र के रूप में बांधता है और कोई विचलन इसे कमजोर कर सकता है। भारत असाधारण विविधता का घर है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र और जाति के रूप में पाई जाती है। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा की भावना प्रदान करता है, भले ही उसका धर्म, क्षेत्र, भाषा या नस्ल देश भर में कुछ भी क्यों न हो। यदि देश में एक से अधिक कानून हों तो यह विसंगति विभाजनकारी सिद्ध हो सकती है। भारत की संवैधानिक एकता की सशक्त पुष्टि करते हुए भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 मे मामले में दिए निर्णय के पीछे दार्शनिक और विधिक तर्कों को सही ठहराया। प्रधान न्यायाधीश का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब देश में कुछ राजनीतिक शक्तियां केन्द्र-राज्य संबंधों पर सवाल उठा रही हैं और वे संघीय ढांचे में राज्यों को ज्यादा अधिकारों की पैरोकारी कर रही हैं। नागपुर में 'संविधान प्रस्तावना पार्क' के उद्घाटन तथा डा. बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर प्रधान न्यायाधीश गवई ने जोर दिया कि भारत की एकता के लिए 'केवल एक संविधान' बहुत जरूरी है और इस विचार की जड़ें स्वयं डा. अंबेडकर के दृष्टिकोण में निहित हैं। यह केवल प्रतीकात्मक संकेत नहीं है। यह न्याय के विचार में निहित विधिक, नैतिक एवं ऐतिहासिक तत्व है। एक राष्ट्र का विचार एक संविधान से शासित होना चाहिए और यह केवल प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि यह गणतंत्र के प्रति मूल निष्ठा का आधार है। डा. बी.आर. अंबेडकर ने लगातार कहा था कि विविधतापूर्ण देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए एक संवैधानिक ढांचा बनाए रखना बहुत जरूरी है। अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान अपनी भावना से संघीय व एकात्मक, दोनों है और यह विविधता को एक केन्द्रीय एकता में समाहित करने में सक्षम है। जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान और विशेष दर्जा रखने की अनुमति देने वाला अनुच्छेद 370 इस प्रकार इस मूल दृष्टिकोण के विपरीत था। संविधान अपनी संरचना में संघीय होने के साथ ही संकट, युद्ध या विखंडन के समय केन्द्र को समुचित शक्तियां देता है। अंबेडकर ने यह कहते हुए इस ढांचे का बचाव किया था कि भारतीय संविधान शांति एवं टकराव में एकजुट रहने के लिए बनाया गया है।

हालांकि, अनुच्छेद 370 को एक अस्थाई प्राविधान के रूप में शामिल किया गया था, पर इसने प्रभावी रूप से समान नागरिकता नियम का एक अपवाद तैयार कर दिया था। इस अनुच्छेद के कारण जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान रखने, विशेषाधिकारों का आनन्द उठाने तथा बाकी भारत से एक विधिक एवं राजनीतिक अलगाव की भावना पैदा करने में सक्षम बनाया था। उम्मीद थी कि समय बीतने के साथ यह अस्थाई प्राविधान स्वयं कमजोर होते-होते गायब हो जाएगा, पर यह एक ढांचागत विसंगति के रूप में बना रहा। जब संसद ने 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया तो इसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश गवई को शामिल करने वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दिसंबर, 2023 में इस निर्णय को उचित ठहराया था। यह फैसला इस बात की घोषणा थी कि भारत का शासन-प्रशासन सच्ची संवैधानिक भावना से चलाया जाना चाहिए जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून और एक ही अधिकार लागू हों, भले ही उनका धर्म चाहे जो हो। चाहे कोई केरल में रहता हो या कश्मीर में, वह कानून के समक्ष समान है और यह बात सिद्धान्त के साथ ही असली जीवन स्थितियों में भी सही है। हमारा संविधान इसी बात की गारंटी देता है। किसी भी देश में विखंडित कानूनी ढांचा विभाजित पहचानों को पैदा करने का काम कर सकता है। इसके उलट एक संवैधानिक व्यवस्था सभी नागरिकों में स्वामित्व व उद्देश्य की समान व साझा भावना को प्रोत्साहित करती है। जब हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को देखते हैं तो वहां संवैधानिक व्यवस्था टूटने के उदाहरण सामने आते हैं। ऐसे में भारत अपने मजबूत संविधान के साथ एकता और अखंडता के मजबूत प्रतीक के रूप में खड़ा दिखता है।

आपातकालः संविधान पर भयानक प्रहार

1975 का आपातकाल कानून-व्यवस्था का अस्थाई स्थगन होने के बजाय भारतीय संविधान की आत्मा पर संपूर्ण हमला था। संविधानवाद की भावना समाप्त होने पर विधिक उपकरणों से लोकतंत्र को आसानी से विकृत किया जा सकता है।

प्रह्लाद जोशी
(लेखक, केन्द्रीय मंत्री हैं)

25 जून, 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। इस निर्णय ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को 21 महीनों के लिए एक तानाशाही शासन में बदल दिया। इसके दौरान भारतीय राज्य में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, प्रेस सेंसरशिप, नागरिक स्वतंत्रताओं का स्थगन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से तोड़ने जैसी घटनायें सामने आईं। हालांकि, आपातकाल को 'आंतरिक अशांति' के नाम पर थोपा गया था, पर वास्तव में यह इंदिरा गांधी के अधिकार के समक्ष राजनीतिक और न्यायिक चुनौतियों की सीधी प्रतिक्रिया थी। यह प्रतिक्रिया खासकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा चुनावी कदाचारों में उनको दोषी ठहराने के बाद आई थी। आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थानों को नुकसान पहुंचाया गया था। किसी भी लोकतंत्र का आधार उसकी संस्थायें होती हैं जिनमें संसद, न्यायपालिका, प्रेस तथा स्वतंत्र विधिक संस्थायें शामिल हैं। आपातकाल के दौरान इनको व्यवस्थित रूप से नुकसान पहुंचाया गया।

उस समय संसद केवल कार्यपालिका की इच्छा पर सहमति देने वाली औपचारिक संस्था बन गई थी। अपने प्रचंड बहुमत के कारण सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने बिना वास्तविक बहस के कठोर कानूनों और संशोधनों को पास कर दिया। न्यायपालिका को गुलाम बना लिया गया था। सरकार ने सक्रिय रूप से न्यायिक नियुक्तियों, स्थानान्तरणों या जजों की पदोन्नति में सीधे हस्तक्षेप किया। ऐसा खासकर नापसंद फैसलों की प्रतिक्रिया में किया गया। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में जस्टिस एच.आर. खन्ना के असहमत निर्णय के मामले में किया गया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन का अधिकार भी स्थगित रहने का निर्णय दिया था। इस प्रकार जस्टिस खन्ना न्यायिक स्वतंत्रता के विरले प्रकाश स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आए थे। प्रेस की स्वतंत्रता लगभग समाप्त कर दी गई थी। पूर्व-सेंसरशिप आदेशों तथा जेल की धमकियों के कारण अखबारों को बंधक बना लिया गया। उल्लेखनीय है कि 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने इस सेंसरशिप के मौन विरोध में अपना संपादकीय खाली छोड़ा था। चुनाव आयोग तथा सीएजी से उनकी स्वायत्तता छीन ली गई थी और उनको कार्यपालिका के आदेश मजबूत करने के लिए औजारों की तरह प्रयोग किया गया था।

आपातकाल का सर्वाधिक खतरनाक आयाम राष्ट्रपति के आदेश से मूलाधिकारों को स्थगित रखना था। अनुच्छेद 14-कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19-भाषण, एकत्र होने व आवागमन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21-जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा अनुच्छेद 22-मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण को या तो स्थगित किया गया अथवा निरर्थक बना दिया गया। क्रूर 'मेंटिनेंस आफ इंटरनल सिक्यूरिटी एक्ट'-मीसा तथा 'डिफेंस आफ इंडिया रूल्स' के अंतर्गत 100,000 से अधिक लोगों को बिना सुनवाई के गिरफ्तार किया गया। इनमें से बहुसंख्य राजनीतिक विरोधी, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, छात्र नेता, पत्रकार व एक्टिविस्ट थे। निरोधक नजरबंदी सामान्य बात हो गई थी और उसका प्रयोग विरोध को कुचलने तथा भय पैदा करने के लिए किया गया। इसके साथ ही शहरी विकास और जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर अनेक कदम उठाए गए। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा शुरू किए गए जबरन बंध्याकरण अभियानों के माध्यम से ज्यादातर गरीब लोगों पर निशाना लगाया गया। लाखों लोगों को जबरदस्ती व धमकी देकर बंध्य बना दिया गया। दिल्ली के तुर्कमान गेट में मलिन बस्तियों को ध्वस्त करने में अनेक लोगों की मौत हुई और उनको जबरन विस्थापित किया गया। सुरक्षा बलों ने यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे निवासियों पर गोली चलाई थी। भय के द्वारा विरोध कुचलने के लिए अत्याचार और क्रूरता का सहारा लिया गया। आपातकाल को व्यापक रूप से अधिकार स्थगित करने तथा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों के रूप में जाना गया, पर इस ज्यादा परेशान करने वाले तथ्य को मोटेतौर से अनदेखा किया गया कि विरोध को कुचलने तथा राजनीतिक बंदियों का साहस तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर शारीरिक व मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न का सहारा लिया गया। हजारों एक्टिविस्टों, छात्रों तथा विपक्षी कार्यकर्ताओं को न केवल जेलों में बंद किया गया, बल्कि हिरासत में उनके साथ क्रूर एवं अपमानजनक व्यवहार किया गया जो स्पष्ट रूप से मूलभूत मानव गरिमा तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन था।

सर्वाधिक भयानक घटनाओं में लारेंस फर्नान्डीज व सुरेश कुमार का उत्पीड़न है। ये दोनों राजनीतिक एक्टिविस्ट तथा सरकार के मुखर आलोचक थे। जार्ज फर्नान्डीज के भाई लारेंस फर्नान्डीज सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और उनको बड़ौदा डायनामाइट कांड में गिरफ्तार किया गया था जिसे पूरी तरह से राज्य के खिलाफ गलत ढंग से विध्वंसकारी योजना के रूप में पेश किया गया था। उनका उत्पीड़न किया गया, बिजली के झटके दिए गए तथा लंबे समय तक तनहाई में बंद रखा गया। लेकिन उत्पीड़न के बावजूद लारेंस फर्नान्डीज ने राजनीति से प्रेरित और आधारहीन आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एबीवीपी से जुड़े युवा छात्र सुरेश कुमार को बैंगलुरू से गिरफ्तार किया गया तथा उनके साथ कठोर व अमानवीय व्यवहार किया गया। इसी प्रकार असंख्य लोगों की व्यवस्थित रूप से पहचान कर उनमें भय पैदा करने के लिए उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया। आपातकाल लागू करने में संवैधानिक मानकों तथा प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई। आपातकाल की जिस तरह घोषणा की गई और उसे बनाए रखा गया वह संवैधानिक प्रक्रियाओं की खुली अनदेखी थी। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह से काम करना होता है। लेकिन आपातकाल लागू करने के पहले कैबिनेट से सलाह तक नहीं ली गई। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने केवल इंदिरा गांधी की संस्तुति पर देर रात यह घोषणा जारी कर दी और इस प्रकार कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी के संवैधानिक प्राविधान का उल्लंघन किया। एकपक्षीय रूप से कानून पास किए गए। इनमें सर्वाधिक विकृत उदाहरण संविधान का 42वां संशोधन था जिसका मूल उद्देश्य संविधान को कार्यपालिका के पक्ष में बदल देना था। 42वें संशोधन कानून, 1976 को 'मिनी संविधान' कहा जाता है क्योंकि यह भारत के इतिहास का सर्वाधिक व्यापक संविधान संशोधन था।

इसके माध्यम से न्यायपालिका का समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया तथा राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना अनिवार्य बना दिया गया। इसके माध्यम से संविधान की उद्देशिका में 'समाजवादी' व 'पंथनिरपेक्षता' शब्द शामिल किए गए, विधायिकाओं का कार्यकाल तथा आपातकाल का विस्तार 5 से 6 साल किया गया। इसके साथ ही संविधान के किसी संशोधन को न्यायपालिका के दायरे से बाहर रखा गया। लेकिन प्रक्रियागत तोड़फोड़ इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि संशोधन को जल्दी से पेश कर पास कराया गया। यह विधेयक संसद में शनिवार 1 नवंबर, 1976 को पेश किया गया और दो दिन के भीतर न्यूनतम बहस तथा विपक्ष की अनुपस्थिति या बहिष्कार के बीच इसे दोनों सदनों द्वारा पास करा लिया गया। इसकी घोषणा रविवार, 19 दिसंबर, 1976 को जारी की गई। शनिवार को संसद खोलने का निर्णय अभूतपूर्व था और यह काम संशोधन को मीडिया व राजनीतिक ध्यानाकर्षण से बचाने के लिए किया गया। आपातकाल में सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया जिनमें भारतीय जनसंघ, समाजवादी, कांग्रेस-ओ तथा ट्रेड यूनियन नेता शामिल थे। नेताओं में सरकार के खिलाफ जनान्दोलन के जनक जयप्रकाश नारायण-जेपी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी तथा जनसंघ के अन्य नेता शामिल थे। जार्ज फर्नान्डीज की गिरफ्तारी और सुनवाई सनसनीखेज बड़ौदा डायनामाइट कांड में हो रही थी। इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य विश्वसनीय विपक्ष को कुचलना तथा बिना चुनौती के शासन करना था। 1975 का आपातकाल जर्मनी में 1930 के दशक में एडोल्फ हिटलर के तानाशाही शासन की तरह था। 1975 का आपातकाल केवल कानून-व्यवस्था का अस्थाई स्थगन होने के बजाय भारतीय संविधान की आत्मा पर संपूर्ण हमला था। इसने दिखाया कि संविधानवाद की भावना समाप्त होने पर विधिक उपकरणों से लोकतंत्र को आसानी से विकृत किया जा सकता है। यह हमारे लिए एक कठोर चेतावनी के रूप में सामने आता है कि लगातार सतर्कता स्वतंत्रता के लिए जरूरी है।

डॉक्टरों के स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें

"इस डॉक्टर्स डे पर हमें यह याद रखना चाहिए कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और उनकी देखभाल हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।"

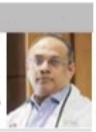

डॉ. राहुल भार्गव
(लेखक फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक हैं)

हर साल की तरह इस बार भी जुलाई की पहली तारीख को हम डॉक्टर्स डे मना रहा हैं और मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल की थीम पर आधारित इस डॉक्टर्स डे को मैं बेहद अहमियत भरा देखता हूं। यह थीम न सिर्फ डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफसहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों के योगदान को पहचानने का एक तरीका उद्धृत करता है बल्कि बीते दशक से शुरू में आए कोविड19 या कोरना से शुरू हुई महामारी के दौरान उनके संघर्ष, बलिदान और निःस्वार्थ सेवा भाव को भी उजागर करता है। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जैसे-जैसे अंतर महाद्वीपीय रूप में कोरोना फैला, हर वर्ग के लोगों ने मास्क की अहमियत और उसकी आवश्यकता को भी पहचाना। इसमें कोई दो राय नहीं कि मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल का संदेश बहुत गहरा और व्यापक होने के साथ ही भावनात्मक भी है जो कोविड19 महामारी में डॉक्टरों और नर्सों द्वारा किए गए अद्वितीय कार्यों को समर्पित है, बल्कि यह उनके निरंतर संघर्ष की ओर भी इशारा करता है, जिनकी देखभाल से हम सभी को जीवन मिलता है। यह थीम उन स्वास्थ्य कर्मियों की भी देखभाल की आवश्यकता को दिखाती है, जो हमेशा दूसरों के इलाज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की ओर कम ध्यान देते हैं।

जब हम डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह लोग न केवल अपने मरीजों के लिए बल्कि समाज के लिए भी जीवन रक्षक होते हैं। कोविड19 जैसे वैश्विक संकट के दौरान उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल की। मास्क और पीपीई किट्स के पीछे उनके चेहरे छिपे होते थे लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी- मानवता की सेवा। उस महामारी में देखभाल करने वाले पेशेवरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की अक्सर अनदेखी की

जाती रही। वे थककर चूर हो गए फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों को सहर्ष निभाया। ऐसे में इस थीम के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें उनके आत्मबलिदान और संघर्ष को पहचानने के साथ-साथ उनकी देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना चाहिए।

डाक्टर्स डे का एक मतलब यह भी है कि हमें डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता और समर्थन बढ़ाने की जरूरत है। जब वे दिन-रात काम कर रहे होते हैं तो उनके पास खुद के लिए समय नहीं होता। उनके लिए एक मानसिक और शारीरिक पुनर्संतुलन की आवश्यकता है ताकि वे अपने पेशेवर कर्तव्यों को पूरा कर सकें। इस थीम के माध्यम से हम यह संदेश देते हैं कि हमें केवल मरीजों का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए बल्कि उन पेशेवरों की देखभाल करनी चाहिए जो हमें स्वस्थ रखने के लिए हर दिन अपनी जान की बाजी लगाते हैं। इस विचारधारा को बढ़ावा देने से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में एक स्थिर और सहयोगात्मक माहौल बना सकते हैं।

कोविड19 जैसी महामारी में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया। जब वे लगातार संक्रमण के खतरे में रहते हुए दूसरों का इलाज करते हैं तो उनके मनोबल को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस थीम का उद्देश्य यह भी है कि हम उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील हों और उन्हें पर्याप्त समर्थन प्रदान करें। कोविड महामारी के दौरान एक वर्ग ऐसा था जो आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ था और उसमें मीडिया भी एक था, उस दौरान न सिर्फ प्रिंट व आनलाइन बल्कि अनेक इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों से मैं व्यक्तिगत तौर पर मुखातिब हुआ। उस दौरान जिन लोगों से मैं मिला उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों के संघर्ष को भलीभांति समझा मौजूदा समय में जब उस दौर के विचारों को उनके साथ हम साझा करते हैं तो डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के समर्पण का जिक्र जरूर होता है।

डॉक्टर्स डे-2025 की यह थीम हमें यह समझने का अवसर देती है कि स्वास्थ्य कर्मियों का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण होता है। उनके पास समय की कमी होती हैए फिर भी वे अपने मरीजों को पूरी तरह से समर्थन और सहानुभूति प्रदान करते हैं। यह थीम हमें यह सिखाती है कि समाज को डॉक्टरों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाने चाहिए। इस थीम के माध्यम से हम यह संदेश भी प्राप्त करते हैं कि हमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उनके संघर्ष और बलिदान को पहचानते हुएए समाज को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनका काम सिर्फ एक पेशेवर जिम्मेदारी नहीं है बल्कि यह समाज के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है।

अंत में मैं यही कहूंगा कि 2025 की डॉक्टर्स डे की थीम न केवल हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सम्मानित करने का एक तरीका है बल्कि यह एक कड़ा संदेश भी है कि हमें उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। वे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सेवा करते हैं इसलिए उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं लोगों से आग्रह भी करना चाहूंगा कि इस दिन हमें स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सभी आवश्यक सहायता मिल रही है ताकि वे अपना काम निडर होकर और पूरी निष्ठा के साथ कर सकें। इस डॉक्टर्स डे पर हमें यह याद रखना चाहिए कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है और उनकी देखभाल हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

आप की बात

पुरी में भगदड़

पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ से तीन श्रद्धालुओं की मौत व 50 से अधिक घायल होने की खबर चिंताजनक है। देश में ऐसे आयोजनों के दौरान भगदड़ की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे देश में ही भगदड़ के कारण होने वाली घटनाओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। यह तो जगजाहिर बात है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में देश व विदेश से श्रद्धालु आते हैं। तो भीड़ नियंत्रण के आवश्यक ठोस उपायों को अपनाया जाना था। साथ ही दुखद तथ्य है कि यहां पर भी वीआईपी संस्कृति फिर भारी पड़ी है। आखिरकार ऐसे अवसरों पर यह वीआईपी कल्चर क्यों नहीं रोका जाता है। भगदड़ का एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि ट्रक के घुसने से यह घटना घटी। सवाल है कि श्रद्धालुओं की इतनी संख्या होने के बावजूद उस रास्ते पर ट्रक जाने से क्यों नहीं रोका गया? ऐसे आयोजनों व अवसरों पर जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है। देश में बार-बार ऐसी घटनाओं को देखते हुए एक मानक कार्रवाई प्रक्रिया बना कर उसका सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना चाहिए। बड़े धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनायें भारत की छवि सारी दुनिया में खराब करने का काम कर सकती हैं। इनसे बचना होगा।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, उज्जैन

जातीय वैमनस्य को हवा

राष्ट्र के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश में एक ऐसा वर्ग सक्रिय हो चुका है जिसका कार्य ही समाज में जातीय वैमनस्य को बढ़ावा देना है। यदि ऐसा न होता तो देश भर में घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं में वह पीड़ित या अपराधी की जाति न खंगालता तथा छोटी-छोटी घटनाओं को जातीय रंग देकर समाज में वैमनस्य फैलाने का दुस्साहस न करता। लम्बे समय से देखा जा रहा है कि कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियां सनातन संस्कृति में साझा समरसता को खंडित करने हेतु कभी यादव और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष के बीज बोते हैं, कभी राजपूत और अन्य जातियों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने का प्रयास करते हैं। विघटनकारी शक्तियां केवल सनातन संस्कृति में जीवन यापन कर रहे हिन्दुओं के मध्य ही अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण की खाई चौड़ी करने में जुटी हैं। यदि ये आपराधिक घटनाएं तथाकथित विघटनकारी तत्वों की जाति तथा गैर हिन्दुओं के मध्य घटित होती हैं तब ऐसे तत्व चुप्पी साध जाते हैं। इससे इनकी नीयत और नीति का खुलासा स्पष्ट रूप से हो जाता है। इसकी जितनी निंदा की जाएए वह कम है। ऐसे विघटनकारी तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के साथ सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है।

– **सुधाकर आशावादी**, मेरठ

गौ संरक्षण का प्रयास

भारत संस्कार और संस्कृति वाला देश है। इस पावन भूमि पर गाय को हमारी माता का दर्जा मिला है और समय-समय पर गौ पूजन भी होता है। गायों के उचित सरक्षण और देखभाल के लिए मध्य प्रदेश की गौशालाओं मे अब गायों की डिजिटल तरीके से हाजिरी लगेगी। पशुपालन विभाग ने इस दिशा मे नई तकनीक लागू कर प्रदेश की करीब 4 लाख गायों के शरीर मे माइक्रो चिप लगाई जाएगी। चिप मे हर गाय की पूरी जानकारी दर्ज होगी! जैसे उसकी नस्ल, उम्र, गर्भधारण की स्थिति, दुधारू क्षमता और गौशाला मे आने की तारीख। इसके साथ ही गली, मोहल्लों, सड़कों और चौराहो पर लावारिस गायों के संरक्षण के प्रयास भी होने चाहिए। इनके कारण कई बार यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटना की परिस्थिति निर्मित हो जाती है। पशु पालकों को सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि वे अपनी गायों को इस प्रकार सड़कों पर घूमने के लिए न छोड़ें। लावारिस गायों को गौशालाओं में ले जाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की टीम बनाई जानी चाहिए। इसमें गौ संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं व स्वयंसेवकों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। गौ संरक्षण के प्रयासों को व्यापक बनाने और जनता तक पहुंचाना जरूरी है।

– **योगेश जोशी**, बड़वाह

ओडिशा में त्रासदी

ओडिशा के पुरी में भगवान् जगन्नाथ की रथयात्रा में प्रशासन की बदइंतजामी के चलते 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई और 100 से अधिक घायल हो गए। हमारा देश धर्मप्राण देश है, जहाँ धार्मिक आयोजन, उत्सव व त्यौहार बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाये जाते हैं। कहीं एक दिन तो कहीं एक से अधिक दिन व कहीं हजारों तो कहीं लाखों की भीड़ उत्सवों में बनी रहती है। यह बात स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक को मालूम रहती है और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उसी की होती है ताकि उत्सव, त्यौहार, आयोजन सानंद संपन्न हो सके। ऐसे में सवाल है कि प्रशासन व सरकार के नुमाइंदे आखिर इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं कि अक्सर आयोजन में भगदड़ मच जाती है और अनहोनी हो जाती है। क्यों नहीं आयोजन के अनुसार सुरक्षा का माकूल इंतजाम किया जाता है? जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी सही तरह से क्यों नहीं निभा पाते हैं? ऐसी भगदड़ वाली घटनाओं की त्वरित जांच कर दोषियों को फौरन सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। केवल मुआवजे की घोषणा समस्या का समाधान नहीं है।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 1 जुलाई 2025

हिंदी पर यू-टर्न

लंबी रस्साकशी और कशमकश के बाद आखिरकार महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई से जुड़े मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींच लिए। प्रदेश की राजनीति में यह मुद्दा जिस तरह से गरमाता जा रहा था, उसे देखते हुए सरकार के पास कोई और विकल्प भी नहीं रह गया था।

विपक्ष का हथियार । फडणवीस सरकार की ताजा घोषणा को इस सचाई से अलग करके देखना मुश्किल है कि हिंदी का मुद्दा राज्य में विपक्षी दलों के हाथों का एक ताकतवर हथियार बनता जा रहा था। न केवल विपक्ष के सभी दल इस मसले पर एकजुट और विधानसभा के मॉनसून सत्र को हंगामेदार बनाने पर आमादा थे, बल्कि ठाकरे बंधुओं को भी हिंदी विरोध की राजनीति की अपनी जानी-पहचानी जमीन वापस मिलती दिख रही थी।

राज्य सरकार ने हाथ खींचे

ठाकरे सीनियर का दौर । याद किया जा सकता है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शुरुआती दौर में पार्टी खास तौर पर हिंदीभाषियों के विरोध के लिए जानी जाती थी। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों की निरंतर बढ़ती आबादी को शिवसेना मराठी अस्मिता के लिए खतरे के रूप में देखती थी। हालांकि बाद के दौर में, खासकर नब्बे के दशक से BJP के गठबंधन में शिवसेना की राजनीति भी हिंदी से हिंदू की ओर मुड़ती गई। मुंबई और महाराष्ट्र की बदलती डेमोग्राफी ने भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना को लचीला रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं, पुरानी आक्रामकता जारी रखते हुए राज ठाकरे की पार्टी धीरे-धीरे कमजोर ही होती गई।

आबादी का बदलता अनुपात । चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र, कुल आबादी में हिंदीभाषियों का बढ़ता अनुपात भी अपना असर दिखा रहा था। 2001 की जनगणना के मुताबिक हिंदीभाषियों की संख्या मुंबई में 25.9% और मराठीभाषियों की 42.9% थी जो 2011 में क्रमशः 30.2% और 41% हो गई। महाराष्ट्र में इसी अवधि में जहां मराठीभाषी आबादी 76% से 73.4% पर आ गई, वहीं हिंदीभाषियों का अनुपात 7.3% से बढ़कर 9.5% हो गया।

घिर गई सरकार । मतदाताओं का बदलता स्वरूप राजनीति में अघोषित तौर पर जो बदलाव ला रहा था, उसे अचानक ही कथित तौर पर हिंदी लादने के इस फैसले ने मानो अप्रासंगिक कर दिया। न केवल विपक्ष की सारी पार्टियां इस सवाल पर आक्रामक रूप में सामने आईं बल्कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी खुलकर इस फैसले का विरोध कर दिया। एकनाथ शिंदे भी इसके पक्ष में नहीं थे। जाहिर है, सरकार इस मुद्दे पर घिर गई थी। ऐसे में उसे इस मुश्किल से निकलने का रास्ता फैसले को वापस लेने में ही दिखा।

नज़रिया

डॉक्टरों की रेटिंग

डॉ. अभिषेक शुक्ला

आज डॉक्टरों को भी रेटिंग दी जाती है, जैसे वे प्रॉडक्ट हों। यह पारदर्शिता के नाम पर हो रहा है। कुछ अरसा पहले डॉक्टर और मरीज के रिश्ते का आधार विश्वास और संवेदनशीलता थी। आज मरीज 'क्लाइंट' और डॉक्टर 'प्रोवाइडर' हैं। अस्पताल मरीज को डिस्चार्ज करते वक्त फीडबैक फॉर्म देते हैं और सोशल मीडिया पर 'बेस्ट डॉक्टर इन टाउन' के मेसेज वायरल होते हैं।

ऑनलाइन प्लैटफॉर्म्स पर मरीज डॉक्टर को रेट करते हैं। लेकिन समझना होगा कि इलाज कोई गारंटी वाला प्रॉडक्ट नहीं है, और न ही डॉक्टर कोई सेल्स एजेंट। कोई डॉक्टर चाहे पूरी निष्ठा से इलाज करे, अगर वांछित परिणाम नहीं आया तो उसकी रेटिंग गिर जाती है। इससे डॉक्टर की छवि तो प्रभावित होती ही है, वह मानसिक दबाव में भी आ जाता है। एक डॉक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है ईमानदारी, लेकिन जब उसका करियर रेटिंग से प्रभावित होने लगे तो वह सच कहने से भी डरता है। पेशेवर दबाव के अलावा इसका भावनात्मक पहलू भी है। डॉक्टर दिनभर की ड्यूटी के बाद जब रेटिंग चेक करता है और एक अनाम मरीज ने सिर्फ 'चेहरा गंभीर था' कहकर डॉक्टर को 2 स्टार दे दिया, तो उससे वह गहरे आहत होता है। खासकर, युवा डॉक्टरों के लिए यह बहुत कठिन होता है, जो मेडिकल स्कूल से निकलते समय आदर्शों से भरे होते हैं। वे भी जल्दी सीख जाते हैं कि यहां इलाज से ज्यादा 'इंप्रेशन' मायने रखता है।

इसका ये मतलब नहीं कि मरीजों को अपनी बात रखने का हक नहीं है। फीडबैक बिल्कुल लिया जाना चाहिए। लेकिन मरीज या उसके परिजनों की हर शिकायत डॉक्टर की लापरवाही नहीं होती। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो संतुलित हो, पारदर्शी हो और डॉक्टरों की गरिमा भी बनाए रखे। कॉरपोरेट अस्पतालों को भी समझना होगा कि 5 स्टार रेटिंग आखिरी सच नहीं है।

डॉक्टर्स डे के मौके पर, जब हम अपने डॉक्टरों को धन्यवाद दे रहे हैं तो एक बात और सोचें कि डॉक्टर भी इंसान है। ज्यादातर डॉक्टर दिन-रात काम करते हैं, कई बार तो स्वास्थ्य और शांति की कीमत पर। असल में, हमें ऐसी संस्कृति बनानी होगी, जहां डॉक्टर को उसकी मेहनत, ईमानदारी और संवेदनशीलता के लिए पहचाना जाए, न कि सिर्फ रेटिंग के आधार पर आंका जाए।

बोल वचन

सब कुछ सेत में

राहुल पाण्डेय

कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जो सीधे आपके घर या शहर का पता बता देते हैं। कल मंडी में आम लेने गया। मोलभाव करते-करते जब दुकानदार परेशान हो गया तो झल्लाकर बोला, 'भैया, तुम सेत में ही ले जाओ।' सेत सुनते ही मैंने उससे पूछा, 'फैजाबाद के हो या सुल्तानपुर के?' वह बोला, 'आपको कैसे पता?' मैंने कहा, 'तुमने सेत बोला, इससे पता चला।' अवध की ओर सेत का मतलब होता है फ्री, यानी मुफ्त। मसलन, हरी मटर के मौसम में जब मंडी से मैं ढेर सारी सस्ती मटर लेकर घर आऊं तो अम्मा पूछें, इतनी सारी? सेत में बंट रही थी क्या? लेकिन कहीं-कहीं इसका प्रयोग सेतु यानी पुल के तौर पर भी होता है। कुमाउंनी में सेत बीजों को अंकुरित करने के लिए पत्तों से ढक कर सेना होता है। बिल्कुल वैसे ही, जैसे चिड़िया अपने अंडे सेती है। गढ़वाली में भी सेत का अर्थ इसी गर्मी से है, भले वो भाप से पहुंचाई जाए। बुंदेली में सेत पुल है तो मर्यादा भी है। ब्रज में सेत उस पार को कहते हैं, तो सफेद को भी। मगही में सेत पुल और सफेदी के अलावा परंपरा, व्यवस्था, नियम आदि भी है। मैथिली में सेत की विशेषता गायब होने की है, तो वहां भी यह शब्द सफेद के लिए प्रयोग होता है। जाहिर है, महंगी इंग्लिश को सेत के लिए कोई एक शब्द प्रयोग करने के लिए सस्ता ही नहीं, थोड़ा फ्री भी होना होगा।

AI Image

चाहे रूस-यूक्रेन के बीच का युद्ध हो या इस्राइल और ईरान का, अमेरिका की भूमिका स्पष्ट है

दुनिया में अशांति के पीछे कौन सी ताक़तें हैं

रहीस सिंह

21वीं सदी दुनिया को फिर उस जगह पर ले आई है, जहां प्रॉक्सीज के साथ-साथ प्रत्यक्ष युद्ध भी हो रहे हैं। इन युद्धों में जो दिखता है, केवल वही सच नहीं होता और न ही युद्ध का दायरा वही होता है, जो हमें दिखाई देता है। जैसे, रूस-यूक्रेन युद्ध सिर्फ रूस की महत्वाकांक्षा और यूक्रेन के स्वाभिमान के बीच टकराव का नतीजा नहीं है। यह तो 21वीं सदी की उन चालों का परिणाम है, जो यूरेशिया के लिए चली जा रही हैं।

शीतयुद्ध का नया वर्जन । आज के समय में ऐसे बहुत से फैक्टर मौजूद हैं जो शीतयुद्ध के एक नए स्वरूप की सूचना देते हैं। यह बात अवश्य ही शीतयुद्ध के हक में नहीं जाती कि दुनिया आज दो ध्रुवों में बंटी नहीं, बल्कि कई छोरों पर टिकी नजर आती है जिसे हम बहुध्रुवीय कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शक्ति के केंद्र नहीं हैं। अमेरिका, रूस और चीन शक्ति के ऐसे केंद्र हैं, जो किसी भी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं।

चूहे-बिल्ली का खेल । अमेरिका और चीन के बीच चल रहा चूहे-बिल्ली का खेल अब आगे निकल चुका है जिसके लिए मैदान यूक्रेन, मध्य-पूर्व (ईरान, गाजा, लेबनान और फलस्तीन) और एशिया-प्रशांत (ताइवान सहित साउथ चाइना सी के आसपास के देश) को चुना गया है। पहले दो मामलों में टकराव सतह पर आ चुका है, जहां तक ताइवान का सवाल है, तो वह कभी भी चीन का शिकार हो सकता है।

सही समय का इंतजार । कई बार ऐसा लगता है कि भावी युद्धों की पटकथाएं निरंतर लिखी जा रही हैं, मैदान तलाशे जा रहे हैं, बस सही समय का इंतजार है। वरना नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन (नैटो) अभी तक अस्तित्व में क्यों है? नैटो सदस्यों को रक्षा बजट बढ़ाने के लिए विवश क्यों किया जा रहा है?

जड़ें अमेरिका तक । वैसे भी चाहे रूस-यूक्रेन युद्ध हो या इस्राइल-ईरान युद्ध, इनकी जड़ें अमेरिका तक जाती हैं। 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' के बाद तो पूरी दुनिया ने अमेरिकी भूमिका देख ही ली। दूसरी तरफ ईरान के साथ मॉस्को-पेइचिंग खुलकर भले न आए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य-पूर्व में अमेरिकी खेल को वे देख-सुन नहीं रहे या भविष्य को देखते हुए अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ईरान का न झुकना और उसका मध्य-पूर्व स्थित अमेरिकी एयर बेस अल-उदैद (कतर) पर मिसाइलें दाग देना कुछ तो संकेत देता ही है।

उभर रहे दूसरे ध्रुव । साफ है कि जहां अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों के साथ बनी अलायंस को मजबूत करना चाह रहा है वहीं पेइचिंग, मॉस्को और तेहरान के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। यही नहीं, शंघाई सहयोग संगठन के रूप में एक सैनिक-आर्थिक गठबंधन और ब्रिक्स देश अमेरिकी नेतृत्व वाली पश्चिमी दुनिया को मजबूत चुनौती दे रहे हैं।

शक्तिहीन संस्थाएं । सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोई ऐसा ग्लोबल लीडर नहीं है जो इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं को रोक सके। 1940 के दशक में बनी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं या तो थक चुकी हैं या शक्तिहीन हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में पोस्ट ट्रुथ के आधार पर नेताओं का उभरना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा) जैसी कट्टर राष्ट्रवादी मुहिम ने दुनिया को एक संकट की ओर धकेलना शुरू कर दिया है।

चीन की नजरें । अमेरिका शक्ति अर्जित करने के लिए निरंतर 'स्मॉल स्केल वॉर्स' को रणनीतिक हथियार बनाने की कोशिश में है। वह दुनिया भर में अपने हथियार बेचने की कोशिश में है ताकि उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ताकतवर बना रहे। ट्रंप इसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की उपज हैं। दूसरी तरफ चीन को देखें तो वह एक तरफ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में युद्धोन्मादी वातावरण बनाए हुए है और दूसरी तरफ अपनी 'डेट ट्रैप डिप्लोमैसी' के जरिए दुनिया पर एक नए उपनिवेशवाद को थोप रहा है। उसकी नजर न केवल ताइवान बल्कि अन्य देशों पर भी है।

बड़ी ताकतों का खेल । जरा सोचिए, सीरिया में असद शासन ढहा तो क्या उसे सिर्फ विद्रोहियों ने ढहा दिया? वर्ष 2024 की ग्लोबल फायर पॉवर इंडेक्स में 145 देशों में से 60वें स्थान पर प्रतिष्ठित सीरिया के पास तीन लाख सैनिक, 1500 से ज्यादा टैंक, 3000 से ज्यादा बख्तर बंद वाहन, मिसाइल सिस्टम के साथ-साथ फाइटर विमान और ह्मीमिम व टॉर्टस में मिलिटरी बेस था, उसकी सेना ने दो सप्ताह के अंदर एक मिलीशिया समूह के आगे घुटने टेक दिए, आखिर कैसे? बड़ी ताकतों के खेल के बिना यह संभव नहीं था।

इस्राइली दुस्साहस । हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्राइल का संघर्ष तो ठीक है, लेकिन ईरान पर उसका हमला समझ से परे है। हमला सिर्फ इसलिए कि ईरान परमाणु बम बना लेगा? तो क्या इस्राइल के पास परमाणु बम नहीं हैं? वैसे खतरा तो पाकिस्तान भी बना हुआ है न केवल दक्षिण बल्कि पूरी एशिया के लिए। फिर भी अमेरिका उसे सिल्वर स्पून से फीडिंग करा रहा है।

ट्रंप की भाषा । याद कीजिए एक समय ट्रूमैन यह कहते थे कि दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रामक कार्य होगा, वह अमेरिकी सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसे रोकने को प्रतिबद्ध होगा। आज डॉनल्ड ट्रंप वही भाषा बोल रहे हैं। जाहिर है, बहुत कुछ है जो इतिहास के पन्नों से बाहर आकर धरातल पर दिखने लगा है। दुनिया बंटी हुई और टकराव की स्थिति में है। आज भी साधन की पवित्रता की चिंता कहीं नजर नहीं आती। यही तो शीतयुद्ध का प्रमुख लक्षण है।

(लेखक विदेश मामलों के जानकार हैं)

मल्टी-कल्टीबैगर नहीं चलेगा गुरु, सीधा लिखिए

अखिलेश प्रताप सिंह

पार्क में सुबह-सुबह घुसते ही श्रीमान क पर नजर पड़ी। मिलेंगे, अपने मन की बातें सुनाते रहेंगे, मेरी सुनेंगे ही नहीं। इस ऊब से बचने के लिए मैंने तुरंत उल्टी दिशा पकड़ ली। लेकिन उनकी नजर पड़ चुकी थी। उनने दूर से ही आवाज दी। अब मुड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था।

दुआ-सलाम होते ही उनने बताया कि वह एक मैगजीन शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हंसी-मजाक का एक कोना भी होगा। मेरी बधाई को तवज्जो दिए बिना उन्होंने कहा, आप भी कुछ लिखते-विखते हैं? दिखने में तो पढ़े-लिखे से लगते हैं? आप हंसी-मजाक वाला एक पीस लिख दीजिएगा। आपको भी आनंद आएगा, पब्लिक को भी।

मुझे हैरानी हुई। मैंने खुद पर एक भरपूर नजर डाली। भई, किस कोने से मैं पढ़ा-लिखता दिखता हूं? उनकी गुगली से बचने के लिए मैंने हथियार डालने वाली मुद्रा बनाई। समझाया, जरा सा इधर-उधर हुआ नहीं कि लोग आजकल हंसी-मजाक का बुरा मान जाते हैं। कोर्ट-कचहरी का मामला बन जाता है। पर वह कुछ भी सुनने को राजी न थे। आप लिखिए, मैं संभाल लूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने कंधे पर हाथ मारा।

मरता क्या न करता वाली हालत में मैंने पूछा, शेयर बाजार का आजकल बड़ा हल्ला है। हर दूसरा आदमी मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर मल्टीबैगर ढूंढ रहा है। ऐसी

AI Image

गुस्ताख़ी माफ़

आपाधापी क्यों मचा रखी है? क्या कामधाम से अच्छी कमाई नहीं हो पा रही, जो ऑप्शंस के चक्कर में फ्यूचर दांव पर लगा रहे? श्रीमान क ने कुछ सोच-विचार वाली मुद्रा में कहा, यह विषय पब्लिक के मूड के खिलाफ है, नहीं जमेगा। कुछ दिल को छूता हुआ सा सोचिए।

तो फिर दिल का ही मामला ले लेते हैं। अच्छे-भले फिट-फाट दिखने वालों का दिल अचानक रुक जा रहा है। हवा-पानी ठीक है। बाजार में मिलावटी चीजें नहीं बिक रहीं। पैकेटबंद सामान पर सेहत के लिए दुरुस्त होने का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। सेहत की व्यवस्था पर कुछ हल्का-फुल्का तंज चलेगा? व्यवस्था का मामला आ गया, नहीं चलेगा। श्रीमान क ने तुरंत ही खारिज कर दिया।

तब पॉलिटिक्स पर कुछ? यह तो मनोरंजन का हॉट टॉपिक है। घर से लेकर ऑफिस तक झिड़की खाने के बाद पॉलिटिक्स और सिनेमा की गपशप ही तो सहारा है दिल बहलाने का। वंशवाद, करप्शन, नेताओं के पाला बदल, ढेरों टॉपिक हैं। जिस पर कहिए, कलम चला दूं।

या फिर कहिए तो रोजगार और महंगाई पर लिख दूं। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन देने पर लिख दूं। कहिए तो मजबूती बता दूं, कहिए तो मजबूरी लिख दूं। या अर्थव्यवस्था की धुआंधार रफ्तार पर लिख दूं। या यह लिख दूं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा घट गई है कि एक बजट में रोजगार की योजना आती है और अगले बजट तक उसे लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती।

श्रीमान क ने मेरी ओर गंभीरता से देखा। कहने लगे, आप जो भी लिखना चाहते हैं, उसमें बहुत घुमावदार रस्ते हैं, कई पेच हैं। ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों नहीं लिखा का बवाल है। पब्लिक को सीधा-सरल किस्सा दीजिए। उसे दिमाग लगाने की जहमत मत दीजिए। उसका मन हरा हो जाए, कुछ ऐसा विषय लाइए। अब यही देखिए कि सावन का महीना आने वाला है। इस महीने सब कुछ हरा-हरा दिखता है। इस पर लिखिए। मैंने हामी भर दी। पूछा नहीं कि उन्हें ही दिखता है या किसी और को भी सावन में सब कुछ हरा-हरा दिखता है?

विशुद्ध राजनीति
पॉलिटॉक

बात कहां तक जाएगी?

एक बार फिर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल TMC नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक होने लगे तो इसे लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। सवाल किया जा रहा है कि पार्टी के दो गुटों के बीच आपसी विवाद महज कुछ मुद्दों को लेकर है या इसकी डोर कहीं और से जुड़ी है? असल में कई महीनों से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने की खबरें भी आती रही हैं। दोनों के बीच अनबन की चर्चा आम चुनाव से पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन तब इसने तूल नहीं पकड़ा। उसकी वजह यह थी कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली थी। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से इस बात के उठने से पार्टी की परेशानी बढ़ सकती है। TMC में एक गुट ममता बनर्जी को ही लीडरशिप रोल में आगे भी देखना चाहता है तो दूसरा गुट दबी जबान से नेतृत्व परिवर्तन की बातें करने लगा है। उसका तर्क है कि लीडरशिप नई हो तो एंटी-इनकंबेंसी को काउंटर किया जा सकता है। जाहिर है, ममता बनर्जी और उनके करीबी नेता इसके खिलाफ हैं। इस बीच, कोलकाता रेप कांड ने ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसलिए चुनाव से पहले नेतृत्व को लेकर यह बहस और तेज हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं, इस पूरे मामले में सबसे अधिक उलझन उन नेताओं को है, जो किसी कैंप के नहीं माने जाते और जिन्होंने वक्त के हिसाब से पोजिशन लेने का मन बनाया है।

मोलभाव में हुआ घाटा

बिहार में एक छोटे क्षेत्रीय दल के नेता हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वह अपने लिए सारे विकल्प खुले रखना चाहते हैं। यह बात सिर्फ आगामी चुनाव की नहीं है। वह अतीत में भी ऐसा कर चुके हैं। राज्य में किस अलायंस के साथ जाना है, इसका फैसला भी नेताजी आखिरी समय में लेते हैं। इस बार भी उन्होंने यही प्लान बनाया हुआ है। पिछले दिनों वह अलायंस की खातिर दबाव बनाने के लिए दिल्ली आए। इसी दिन उन्होंने सुबह में कांग्रेस नेताओं के साथ और शाम में BJP नेताओं के साथ मीटिंग तय कर ली। उन्हें लग रहा था कि दोनों मीटिंग गुप्त रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों खेमों में उनकी मीटिंग की बात लीक हो गई। लिहाजा, इसका असर भी हुआ। अब दोनों पक्ष उनसे अलायंस की बात करने को लेकर सतर्क हैं और इससे नेताजी की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि फिलहाल तो नेताजी इस बात का पता लगाने में मशगूल हैं कि उनकी मीटिंग की बात लीक कैसे हुई? नेताजी का मानना है कि किसी ने उनके साथ साजिश की है। लेकिन वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इससे उनकी बारगेनिंग पावर पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा।

AI Image

जाने क्या होगा

BJP शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अंदरखाने यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि पार्टी, गवर्नेंस और संगठन के स्तर पर ताजगी का संदेश देने के लिए कई मौजूदा मुख्यमंत्रियों को बदल सकती है। कहा जा रहा है कि ऐसा पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद होगा। अब इसके पूर्ण संकेत मिलने लगे हैं कि एक महीने के अंदर नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इस बीच, नए मुख्यमंत्रियों की चर्चा की वजह से मौजूदा मुख्यमंत्रियों की फिक्र बढ़ गई है। इनमें भी एक मुख्यमंत्री सबसे अधिक डरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से वह दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। उनके डर की वजह भी है। कई सहयोगियों ने उनके खिलाफ शिकायतें कर रखी हैं जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें काम करने की खुली छूट भी नहीं मिल पा रही है। उनके राज्य में विपक्ष भी मजबूत है। इन साहब को लग रहा है कि अगर पार्टी ने मुख्यमंत्रियों को बदलने की पहल की तो इस मुहिम का पहला शिकार वही होंगे।

राजनीति के केंद्र में नीतीश

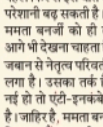

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राज्य की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द सिमट कर रह गई है। तेजस्वी यादव की अगुआई में महागठबंधन यह तय नहीं कर पा रहा है कि नीतीश पर उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर कितनी राजनीति की जाए। वहीं, BJP यह तय नहीं कर पा रही है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए या नहीं। इस असमंजस की ठोस वजह राज्य की राजनीति क पृष्ठभूमि में है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले कुछ वर्षों में दोनों परस्परविरोधी गठबंधनों में रहकर सरकार चलाई है, उसे देखते हुए ये गठबंधन समझ नहीं पा रहे कि भविष्य के उनके कदम की दिशा क्या होगी। खैर, दोनों पक्षों की इस उलझन की वजह से राज्य की राजनीति के केंद्र में फिर से नीतीश कुमार आ गए हैं। दोनों पक्षों की ओर से कराए गए सर्वे के बारे में बताया जा रहा है कि भले 20 सालों के एंटी-इनकंबेंसी का असर है, लेकिन नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक अभी भी टूटा नहीं है। पिछले कई चुनाव से नीतीश कुमार का अपना पारंपरिक वोट ही राज्य के चुनाव की दिशा तय करता रहा है।

ब्रेकअप तय है?

सांसद शशि थरूर के बारे में कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता का कहना है कि अब थरूर जान-बूझ कर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी उन पर एक्शन लें। इस नेता का कहना है कि थरूर ने RSS को लेकर इसी रणनीति के तहत बयान दिया। हालांकि, अभी तक कांग्रेस की रणनीति यही रही है कि थरूर को शहीद होने का मौका न दिया जाए। हां, अगर राहुल गांधी कोई फैसला करते हैं तो बात अलग होगी।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

जीवन में प्रकृति

28 जून को प्रकाशित कवयित्री पार्वती तिर्की का इंटरव्यू 'आदिवासियों का गीत ही साहित्य है' आदिवासी समाज की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, प्रकृति से उसके गहरे संबंध और पारंपरिक ज्ञान की आत्मीयता को दर्शाता है। आदिवासी गीतों में उनके जीवन की कठिनाइयां, उत्सव, रीति-रिवाज बसे हुए हैं। पारिवारिक नोंकझोंक और स्नेह की भी इन गीतों में स्पष्ट झलक मिलती है। गीत तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे हैं। उन्होंने न केवल प्रकृति, स्त्री और समुदाय को केंद्र में रखा, बल्कि यह भी दिखाया कि आदिवासी समाज कैसे इकोलॉजी, समानता और न्याय के गहरे सिद्धांतों पर आधारित है। यह समाज के लिए एक जरूरी सबक है।

सुजीत मंडल, ईमेल से

सफल रहे वार्ता

डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने कनाडा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रविवार देर रात कनाडा ने डिजिटल सर्विस टैक्स (डीएसटी) रद्द कर दिया, जो सोमवार से अमेरिकी टेक दिग्गजों पर लगाया जाने वाला था। ट्रंप ने इसे 'अमेरिका पर हमला' करार देते हुए कठोर टैरिफ लगाने और व्यापार वार्ता तोड़ने की चेतावनी दी थी। कनाडाई वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ट्रंप 21 जुलाई तक नए व्यापार समझौते के लिए वार्ता फिर शुरू करेंगे। वार्ता सफल रही तो यह निश्चित ही दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने का एक अच्छा अवसर हो सकता है।

आर.के. जैन, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

रेलवे रिजर्वेशन चार्ट 4 नहीं, 8 घंटे पहले आएगा- एक खबर।
- चार्ट चाहे जितना भी पहले लाओ, ट्रेन टाइम पर निकाल दिया करो।
मनीषा रावत

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

साधना की भूख बढ़ जाएगी, आप संकल्प तो लीजिए

दादाश्री

हम हर रोज ऐसा क्या करें, जिससे हमारी साधना बनी रहे और हम अपने परिवर्तन के पथ पर बने रहें? मान लीजिए, किसी पार्टी-फंक्शन में आपको आमंत्रित किया जाता है और आपके सामने भोजन की थाली रखी जाती है। अगर आपको भूख ही नहीं है, खाने की इच्छा ही नहीं है, तब आप इस वक्त वह भोजन नहीं कर पाएंगे। आप तभी खाएंगे जब आपको भूख लगेगी।

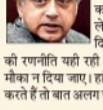

भोजन एक ऐसी चीज है, जिसके लिए रोज-रोज कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। हर दिन सुबह-दोपहर-शाम भोजन करने के लिए आपको कोई याद दिलाएगा, ऐसा भी आप नहीं सोचते हैं। आपको पता है कि जब भूख लगती है तो खाना खाना चाहिए। वैसे ही आपके परिवर्तन की यात्रा में सत्य स्वरूप को जानने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि वह आपकी भूख हो। भूख हो आगे चलने की, अपने आपको समझने की या अपने अस्तित्व का अनुभव करने की, तो आप आगे बढ़ते हैं।

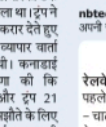

आजकल के जनरेशन को लगता है कि बहुत कुछ अपनी जगह पर ही मिल जाता है। जब कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तो समझ नहीं आता कि यह कैसे। आप सोचते हैं, बहुत शॉर्ट कट तरीके से जल्दी-जल्दी मिल जाए। इसलिए भीतर वह भाव ही नहीं रहा कि परिश्रम करते हुए वहां पहुंचना है। जीवन में सब कुछ पर्याप्त-सा लगता है, तो कभी-कभी यह भाव बन नहीं पाता है कि कुछ करना भी है।

ऐसे आध्यात्मिक प्रगति की राह पर हम यही सोचते लगते हैं कि यह बैठे-बैठे, लेटे-लेटे मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रही बात साधना की, तो कौन-सी साधना करनी है? किस प्रकार की करनी है? यह आपके लक्ष्य के ऊपर, आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। इस संकल्प के अनुसार आप जो कुछ करते हैं, वही आपके कर्म हैं। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो आपको रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करनी है, गाने का रियाज करना है। उसी प्रकार आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, तो आपको खुद अपने लिए साधना बनानी होगी। वह ध्यान हो सकता है, पठन भी हो सकता है। जब आपको संकल्प बताया जाता है कि यह संकल्प है, यह लक्ष्य है आपके जीवन का, तब आप आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर आपकी साधना के लिए आपको भूख लगनी चाहिए और साथ में संकल्प भी हो। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं।

तीसरी महत्वपूर्ण चीज है- गुरु, मास्टर, ईश्वर, परमात्मा। तो पहली बात आती है, भूख है कि नहीं। वह भूख नहीं है तो आप साधना के साथ न्याय नहीं कर पाते। फिर संकल्प नहीं है तो आप साधना के साथ न्याय नहीं कर पाते। आप उठेंगे तो आपके आसपास के लोग भी उठेंगे। यह सोचकर फिर से आप अपनी साधना शुरू कीजिए।

युद्ध जीतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शांति के लिए प्रयास करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। -अरस्तू

आईएलओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आज देश के करीब 95 करोड़ लोग किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ जरूर उठा रहे हैं। बावजूद इसके कि एक दशक से भी कम समय में इस तरह की प्रगति एक बड़ी उपलब्धि है, अब भी चुनौतियां बाकी हैं।

सुरक्षा का दायरा

प्रधानमंत्री मोदी का अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह बताना कि भारत के करीब 95 करोड़ लोग किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ जरूर उठा रहे हैं, सरकार की एक बड़ी उपलब्धि को रेखांकित करता है। उल्लेखनीय है कि 2015 में यह संख्या 25 करोड़ से भी कम थी, और अब एक दशक से भी कम समय में देश की 64 फीसदी आबादी तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं, तो यह प्रगति वाकई प्रशंसनीय है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने गरीबों, बुजुर्गों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आय सहायता प्रदान करने एवं बीमा कवरेज के दायरे में लाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं की न केवल घोषणा की, बल्कि तत्परता से उनके कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में संसद को बताया था कि 31 जनवरी, 2025 तक 8.5 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाया है। देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है, तो 7.65 करोड़ लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। इसके अलावा, ई-श्रम पोर्टल से 30.68 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को लाभ मिल रहा है। इन पंजीकृत श्रमिकों में 53.68 फीसदी से अधिक महिलाएं हैं। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की रिपोर्ट में भारत की इस कामयाबी की चर्चा इस बात का द्योतक है कि तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की केंद्र सरकार की नीति सही पटरी पर है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भी भारत पहली बार 2025 में शीर्ष सौ देशों में शामिल हुआ है, जिससे भारत के समावेशी विकास की राह पर बढ़ने की ही पुष्टि होती है। हालांकि, इस प्रगति के बावजूद चुनौतियां बाकी हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, इसके लिए जमीनी स्तर पर और अधिक प्रयासों की जरूरत है। डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढांचे की कमी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बाधा बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, सीमित राजकोषीय क्षमता, तकनीकी और प्रशासनिक कमियों और जनसांख्यिकीय बदलावों पर ध्यान देने के साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क में शामिल किया जाना भी जरूरी है, ताकि कोई भी नागरिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर न रहे। सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या को सौ करोड़ तक ले जाने के लक्ष्य के मद्देनजर इन चुनौतियों का समाधान जरूरी है।

इतने बुरे भी नहीं नेतन्याहू और ट्रंप

अगर ट्रंप और नेतन्याहू के आलोचक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें हर उस चीज का विरोध करना चाहिए, जिसका ये दोनों समर्थन करते हैं, तो यह आपदा वाली स्थिति ही होगी। मैं भी कोई इन नेताओं का समर्थक नहीं हूं, लेकिन यह मानना ही होगा कि पश्चिम एशिया की सूरत बदलने के लिए जो भी जरूरी था, वह ये कर रहे हैं।

डेविड ब्रूक्स
द न्यूयॉर्क टाइम्स

अलग राजनीतिक झुकाव रखने वाले बहुत से लोगों की तरह मैं भी पिछले कुछ दशकों से इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ रहा हूं। फिर भी मेरे जैसे उनके आलोचकों को एक असहज तथ्य का सामना करना पड़ रहा है कि पिछले 10 महीनों में, नेतन्याहू ने पश्चिम एशिया की सूरत बदलने के अपने उद्देश्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा किया है। उन्होंने हमास और हिजबुल्ला को कमजोर किया है, ईरानी धर्मतंत्र को दयनीय और जीर्ण-शीर्ण बना दिया है। इस्राइल ने अपने दुश्मनों पर अपनी विशाल सैन्य और खुफिया सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया है। इसने दिखा दिया कि इसके एजेंट दुश्मन संगठनों में घुसपैठ कर सकते हैं और उनके आतंकी नेताओं को खोजकर मार सकते हैं।

इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इस्राइल-अमेरिका का हमला भी शामिल है। हमें अब तक नहीं पता कि उस हमले से कितना नुकसान हुआ है। पेंटागन की एक प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया कि हमलों ने ईरानी परियोजना को कुछ महीने पीछे धकेल दिया है। लेकिन विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान सहित कई अन्य रिपोर्टों में पाया गया कि इस हमले ने ईरान के संवर्धन कार्यक्रम को 'प्रभावी रूप से नष्ट' कर दिया।

हम समय रहते जान सकते हैं कि बमबारी से क्या हासिल हुआ। हम यह भी जानते हैं कि इस्राइल और अमेरिका के पास ईरान पर कभी भी और कहीं भी हमला करने की इच्छाशक्ति और क्षमता है। हम जानते हैं कि यदि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पुनः शुरू करता है, तो इस्राइल और अमेरिका के पास इससे भी अधिक विनाशकारी तथा शासन-तंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाली क्षमता है। हम यह भी जानते हैं कि ईरान और उसके सहयोगियों ने सात अक्तूबर, 2023 के बाद से कुछ पागलपन भरी आत्म-विनाशकारी गलतफहमियां पाल ली हैं, जो तेहरान में बैठे धर्म-शासकों के लिए अशुभ संकेत हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सात अक्तूबर, 2023 के हमले पर नेतन्याहू की सभी तरह की प्रतिक्रिया का समर्थन करता हूं। मैं तो बस यह कह रहा हूं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग कम से कम ईरानी खतरे के व्यापक मुद्दे पर अच्छाई की ताकत साबित हुए हैं।

हममें से जो लोग नेतन्याहू और ट्रंप से नफरत करते हैं, उन्हें थोड़ी विनम्रता दिखानी चाहिए और कुछ पुनर्विचार करना चाहिए। खैर, जो कुछ भी हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है कि नेतन्याहू का पिछले कई दशकों से ईरान के प्रति जुनूनी होना सही था। 1979 की ईरानी क्रांति विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। तब से ईरान पश्चिम एशिया में अस्थिरता का मुख्य स्रोत रहा है। उस क्षेत्र के अन्य मुद्दे गौण हैं। पिछले कुछ दशकों में, ईरान ने आतंकवादी लड़ाकों और उन्नत हथियारों के साथ इस्राइल के चारों ओर व्यवस्थित रूप से फंदा बनाया है। अयातुल्ला अली खामनेई ने घोषणा की है कि 2040 में इस्राइल का अस्तित्व नहीं रहेगा।

दशकों से, इस्राइल और अमेरिका, दोनों ही इस फंदे को बर्दाश्त करने को तैयार थे। लेकिन सात अक्तूबर को यह बदल गया। इस्राइल को यह जानकर आश्चर्य और निराशा हुई कि उसके पास जानलेवा हमलों का अनुमान लगाने और उन्हें रोकने की क्षमता नहीं है। अचानक से यह फंदा असहनीय लगने लगा। उसने हिजबुल्ला और ईरानी परमाणु हथियारों की भविष्य की आशंका सहित पूरे फंदे को खत्म करने का प्रयास किया, और अब यह सही निर्णय लगता है।

कभी-कभी मैं लॉन पर लगे साइनबोर्ड देखता हूं कि 'युद्ध इसका उत्तर नहीं है', लेकिन यहां एक ऐसी परिस्थिति थी, जिसमें युद्ध ही इसका उत्तर था। इस्राइल हिजबुल्ला को हराने में सक्षम था, क्योंकि यह अधिक प्रभावी और अधिक शक्तिशाली है। ईरान ने बमबारी का कमजोर जवाब दिया है, क्योंकि वह कम शक्तिशाली है। अन्य अमेरिकी प्रशासनों ने कल्पना की थी कि वे किसी तरह की बातचीत के जरिये ईरान को निष्प्रभावी कर सकते हैं, लेकिन 40 से ज्यादा वर्षों से ईरान ने पश्चिम के साथ मेल-मिलाप से लगातार इन्कार किया है। नेतन्याहू की यह सोच भी सही थी कि कभी-कभी सेना को हराने की तुलना में किसी आख्यान को हराना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।

यह सबक हमें बार-बार सीखना होगा कि हमारे शत्रु वास्तव में हमारे शत्रु हैं। 1930 के दशक में ब्रिटिश सत्ता का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी गया और यह दावा करते हुए लौटा कि हिटलर एक अच्छा व्यक्ति है, जिसके साथ व्यापार किया जा सकता है। वे उस व्यक्ति में निहित बुराई को समझ नहीं सके। ईरान, हमास और हिजबुल्ला के प्रति पश्चिमी प्रतिक्रिया में भी यही नकार का भाव व्याप्त था। लेकिन नेतन्याहू, अपनी तमाम नैतिक कमियों के बावजूद, ईरानी वास्तविकता को उसके असली नाम से पुकारने और उससे स्पष्ट निष्कर्ष निकालने को तैयार हैं।

मैं नेतन्याहू या ट्रंप की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। बल्कि मैं उन दिनों को याद कर रहा हूं, जब इस धरती पर उदारवादी लोग होते थे। एक परंपरा थी, जो ऐसे लोगों से बनी थी, तब लोकतंत्र और मानवाधिकारों के हिमायती थे, लेकिन वे यह भी समझते थे कि एक खतरनाक दुनिया में स्थिरता, शांति और सभ्यता के लिए अमेरिका एक आवश्यक शक्ति है। पर इराक युद्ध की विफलताओं के बाद उदारवादियों की परंपरा खत्म हो गई।

मैं ईरान पर अमेरिकी बमबारी के बाद कई डेमोक्रेटिक नेताओं की प्रतिक्रियाओं को देखता हूं और पाता हूं कि इनमें से कई लोग सहज रूप से यह मानते हैं कि अमेरिकी शक्ति ही दुनिया की पहली समस्या है। वे मानते हैं कि यदि ट्रंप ऐसा करते हैं, तो यह बुरा ही होगा, और इसमें स्वतंत्र सोच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह एक आपदा होगी, अगर नेतन्याहू और ट्रंप के आलोचक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें उन सभी चीजों के खिलाफ होना चाहिए, जिनका वे समर्थन करते हैं। इसका मतलब होगा भेड़ियों को आजाद छोड़ देना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने युद्धविराम के बाद हाल ही में फिर से आशंका जताई है कि ईरान अमेरिका द्वारा नष्ट किए गए परमाणु स्थलों के बावजूद फिर से यूरेनियम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगा। ईरान आसानी से परमाणु हथियार बनाने की अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं है।

©The New York Times 2025

जीवन धारा

पं. श्रीराम शर्मा आचार्य

मनुष्य का कर्तव्य है कि सुख-दुख का ध्यान किए बिना सदैव अपने उत्तरदायित्व का पालन करे और सद्मार्ग पर चलता रहे। कष्टों में सदैव पाप की कल्पना न करें, कई बार इसमें हमारा हित भी छिपा होता है।

कष्टों में भी हमारा हित छिपा होता है

आम तौर पर दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दुखों का कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं है कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ईश्वर की कृपा के कारण, पूर्व संचित पुण्यों के कारण और पुण्य संचय की तपश्चर्या के कारण भी दुख आते हैं। भगवान को किसी प्राणी पर दया करके उसे अपनी शरण में लेना होता है, कल्याण के पथ की ओर ले जाना होता है, तो उसे भवबंधन से, कुप्रवृत्तियों से छुड़ाने के लिए ऐसे दुखदायक अवसर उत्पन्न करते हैं, जिनकी ठोकर खाकर मनुष्य अपनी भूल को समझ जाए, निद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए।

सांसारिक मोह, ममता और विषय वासना का चस्का ऐसा लुभावना होता है कि उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। एक विचार आता है कि जीवन जैसी अमूल्य वस्तु का उपयोग किसी श्रेष्ठ काम में करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण ऐसी लुभावनी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, जिनके कारण वह विचार उड़ जाता है और मनुष्य जहां का तहां उसी तुच्छ परिस्थिति में पड़ा रहता है। इस प्रकार की गंदगी में से निकालने के लिए भगवान अपने भक्त को झटका देते हैं, सोते हुए को जगाने के लिए बड़ी जोर से झकझोरते हैं। दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि उनके जबर्दस्त झटके के आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सजग होकर अपनी भूल सुधार ले और सही मार्ग पर आ जाए। धर्म-कर्म करने में, कर्तव्य धर्म का पालन करने में असाधारण कष्ट सहना पड़ता है। निस्संदेह कुछ दुख पापों के परिणामस्वरूप भी होते हैं। इसी प्रकार जब अपने ऊपर कोई विपत्ति आए, तो केवल यह ही नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, अभागे हैं। संभव है, वह कष्ट हमारे किसी हित के लिए आया हो, उस कष्ट की तह में शायद कोई ऐसा लाभ छिपा हो, जिसे हमारा अल्पज्ञ मस्तिष्क आज ठीक-ठीक पहचान न सके।

हर कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति को पूर्व जन्म का पापी कहना उचित नहीं। इस भ्रम के आधार पर कोई व्यक्ति अपने को बुरा समझे, अपने को निंदित समझे, इसकी जरूरत नहीं है। कर्म की गति गहन है। उसे हम ठीक प्रकार से नहीं जानते, केवल परमात्मा ही जानता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि सुख-दुख का ध्यान किए बिना सदैव अपने उत्तरदायित्व का पालन करे और सद्मार्ग पर चलता रहे। कार्य में सफलता मिलती है या असफलता, प्रशंसा होती है या तिरस्कार प्राप्त होता है, लाभ में रहते हैं या घाटे में, इन बातों के कारण अपने कर्तव्य का त्याग करना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जगत ईश्वरीय न्याय सर्वत्र काम कर रहा है। हम अपनी छोटी बुद्धि से उसे समझें चाहे न समझें, वह जल्दी प्रकट हो या देर से आए, पर हमारे कर्मों का सच्चा फल हमको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हमको किसी भी अवस्था में ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

अपना मूल्य समझें

सूत्र

मनुष्य एक अनगढ़ पत्थर है, जिसे शिक्षा रूपी छेनी और हथौड़ी से सुंदर आकृति प्रदान की जा सकती है। जीवन में गलती सबसे होती है। गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि गलती को न सुधारना बुरा है। हर व्यक्ति को अपना मूल्य समझना चाहिए और खुद पर यह विश्वास करना चाहिए कि वह संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है।

दूसरा पहलू

मशहूर शायर का बचपन आगरा में जहां पतंग उड़ाते हुए बीता था, उस जगह को अब कोई नहीं जानता।

अपने जन्मस्थान में ही बेगाने हो गए गालिब

भूपेंद्र कुमार

करते किस मुंह से हो गुर्बत की शिकायत गालिब। तुम को बे-मेहरी-ए-यारान-वतन याद नहीं।। यानी तुम किस मुंह से दूसरों की शिकायत करते हो, क्या तुम्हें अपने लोगों की बेमुरौवती याद नहीं। उर्दू और फारसी के मशहूर शायर असदुल्लाह बेग खान यानी मिर्जा गालिब ने जब यह शेर लिखा होगा, तो क्या वह अपना मुस्तकबिल (भविष्य) देख रहे थे। कम लोग जानते हैं कि उनका जन्म आगरा में हुआ। यहीं उन्होंने अपना बचपन पतंग उड़ाते व शेरो-शायरी का सलीका सीखते हुए बिताया।

पुराने आगरा शहर के पीपल मंडी के कला महल (काला महल) इलाके को उनका जन्म स्थान बताया जाता है। पर यहां अब इस अजीम शायर की कोई याद बाकी नहीं है। यमुना किनारा रोड से बेलनगंज होते हुए पीपल मंडी के लिए रास्ता जाता है। उनका जन्म कहां हुआ होगा या वह कहां रहते होंगे, इसका बस एक ही निशां बाकी है। वह है 1920 में लिया गया एक धुंधला-सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। इसमें एक इमारत दिखाई देती है। लेकिन आज यह कहां है, कोई नहीं जानता। मुमकिन है कि इस पर किसी ने कब्जा करके नई इमारत तामीर करा दी हो। कुछ किताबों में उनका जन्म स्थान पीपल मंडी की उस इमारत को बताया जाता है, जहां इंद्रभान इंटर कॉलेज है। कॉलेज के कर्मचारी बताते हैं कि आपकी तरह साल में दो-चार लोग जरूर पूछने आते हैं, क्या यही गालिब का घर है। यह इमारत पुरानी तो है, पर गालिब यहां रहते थे या नहीं, यह पता नहीं। इसी के पास राधा स्वामी सत्संग का भवन है। क्या गालिब यहां रहते थे, इसका जवाब आसपास के लोगों के पास नहीं है। कुछ ने तो उनका नाम भी नहीं सुना। गालिब का जन्म आगरा के कला महल इलाके में 27 दिसंबर, 1797 को हुआ। उनके पिता असदुल्ला बेग सेना में थे और यहां उनका ननिहाल था। वह जब चार साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया था। उन्होंने आगरा के उस्तादों से शायरी की तालीम ली। 11 वर्ष की उम्र में शेर कहना व लिखना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में वह दिल्ली चले गए। पर आगरा उनसे कभी छूटा नहीं। गालिब ने 1858 में अपने दोस्त मुंशी शिवनारायण को चिट्ठी लिखी, जिसमें कला महल, खटिया वाली हवेली, कटरा गड़रियान का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा, 'कटरे की एक छत से वह और बनारस के निष्कासित राजा चेत सिंह के बेटे बलवान सिंह पतंग उड़ाते थे।' इस अजीम शायर के नाम पर आगरा में कुछ भी नहीं है। कोई स्मारक, पार्क, सड़क या संग्रहालय या ऐसा कुछ, जिसमें गालिब को सहेजा गया हो। हालांकि, उनके लिए आगरा तो अपना था, शायद तस्वीर की वह हवेली।

गालिब का जन्म कहां हुआ होगा, इसका बस एक ही निशां बाकी है। वह है 1920 में लिया गया एक धुंधला-सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो।

तस्वीर में यही हवेली है, जिसे गालिब की जन्मस्थली माना जाता है।

आंकड़े

रीसाइक्लिंग प्लांट

पर्यावरण संरक्षण के प्रयास रंग ला रहे हैं। देश में बीते पांच वर्षों में कचरे को री-साइकिल करने वाले प्लांटों की संख्या काफी बढ़ी है।

2020	829
2021	2,027
2023	2,057
2024	2,447
2025	3,036

आंकड़े संबंधित वित्त वर्ष में भारत में रीसाइक्लिंग प्लांटों की संख्या के | स्रोत : MoSPI

संत श्रीश्री भट्ट जी ने कल्पना की कि भगवान श्रीकृष्ण और राधिका जी बारिश में नृत्य करते हुए दिखें, तो भगवान उनकी लालसा को पूरा करने के लिए आ गए।

जतन कियो कुछ मैं ना

अंतर्यात्रा
संकलित

निंबार्ककुल के संत केशव काश्मीरी जी के शिष्य श्रीश्री भट्ट जी भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने ब्रज भूमि को छोड़कर अन्य कहीं भी न जाने का संकल्प लिया था। कभी-कभी वह गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। उनके पास जो भी शिष्य बनने के लिए आता, तो वह उसकी कड़ी परीक्षा लेते थे और जब वह समझ लेते थे कि इसका मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, तब उसे मंत्र देते थे।

वह प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते थे- *'बसो मेरे नैननि में दो चंद। गौर बदनि वृषभानुनंदिनी, स्यामबरन नंदनंद।। गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत आनंदकंद। जै श्रीभट्ट प्रेमरस बंधन क्यों छूटै दृढ़ फंद।'* बताया जाता है कि श्रीश्री भट्ट जी की उत्कंठा पूरी करने के लिए भगवान स्वयं आकर उनके समक्ष तरह-तरह की लीलाएं करते थे। एक बार श्रीश्री भट्ट जी यमुना के तट पर बैठकर सघन तमाल-कुंज तथा करील-कदंब आदि को देखकर मल्हार अलापने लगे- *'भींजत कब देखों इन नैना। स्यामजू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना।।'* उन्होंने इतना ही गाया था कि बारिश होने लगी तथा घनश्याम और राधिका जी प्रत्यक्ष भीगती हुई नजर आईं। उस अपार छटा को देखकर श्रीश्री भट्ट जी भक्तिभाव में इतने लीन हो गए कि उन्हें कुछ सुध-बुध भी न रही। इस संबंध में उन्होंने लिखा, *'स्यामा-स्याम कुंजतर ठाढ़े, जतन कियो कुछ मैं ना। श्रीभट उमड़ि घटा चहुं दिसि तें, घिर आई जल सेना।।'*

अमर उजाला
पुराने पन्नों से —— 01 जुलाई, 1950

सियोल पर बढ़ा घमासान अमेरिकी जहाजों की बमबारी

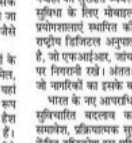

सिहोल पर घमासान
अमरीकन जहाजों की बमबारी

अमेरिकी हवाई जहाजों और समुद्री सेना ने उत्तर कोरिया की सेना पर हमले शुरू कर दिए हैं। सियोल को लेकर चारों ओर घमासान मचा हुआ है। हवाई जहाज बम वर्षा रहे हैं और रॉकेट व मशीनगनों का खुला प्रयोग हो रहा है।

नए आपराधिक कानूनों का एक साल

बीते साल एक जुलाई को लागू हुए नए आपराधिक कानूनों का पहले वर्ष में एक मजबूत आधार स्थापित हो चुका है। अब आवश्यकता है इन्हें और मजबूती से आगे बढ़ाने की।

सुनील कुमार गुप्ता, पूर्व आईपीएस, विधिक एवं प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ | कानून

एक जुलाई, 2024 को भारत ने औपनिवेशिक युग के अपने आपराधिक कानूनों को तीन आधुनिक विधियों से बदल दिया-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए)। इनका उद्देश्य एक नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-सम्मिलित आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण करना था। लागू होने के पहले दो महीनों में ही इन नए प्रावधानों के तहत 5.56 लाख से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं, जो इनकी सक्रिय स्वीकार्यता को दर्शाती है। इसके साथ ही 5.6 लाख से अधिक पुलिस, अभियोजन और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जो प्रशासन की तैयारी और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय न्याय संहिता ने संगठित अपराध, आतंकवाद, और भीड़ हत्या जैसे अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। हालांकि, कई प्रावधान आईपीसी से मिलते-जुलते हैं, पर यह निरंतरता और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने का एक व्यावहारिक तरीका माना जा रहा है।

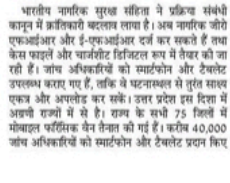

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने प्रक्रिया संबंधी कानून में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। अब नागरिक जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर दर्ज कर सकते हैं तथा केस फाइलें और चार्जशीट डिजिटल रूप में तैयार की जा रही हैं। जांच अधिकारियों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे घटनास्थल से तुरंत साक्ष्य एकत्र और अपलोड कर सकें। उत्तर प्रदेश इस दिशा में अग्रणी राज्यों में से है। राज्य के सभी 75 जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं। करीब 40,000 जांच अधिकारियों को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, 60,000 नए भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें नए कानूनों को शामिल किया गया है, ताकि वे शुरू से ही नई विधिक व्यवस्था में प्रशिक्षित हो सकें। ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली, मालखानों का डिजिटलीकरण और पुलिस थानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों की स्थापना जैसे उपाय सक्रिय रूप से लागू किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश 'ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल' के उपयोग में अग्रणी राज्य है। बीएनएसएस के अंतर्गत मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट्स का विस्तार प्रमुख सुधार है। साथ ही फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) को उन्नत किया जा रहा है, ताकि वे साइबर अपराध और डीएनए परीक्षण जैसे जटिल मामलों की जांच कर सकें।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिजिटल युग की मांगों के अनुरूप साक्ष्य कानून को अद्यतन करता है। अब ईमेल, मेटा डाटा, सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस डाटा और यहां तक कि ब्लॉकचेन रिकॉर्ड को भी कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है। प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हैश वैल्यू और डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिए गए हैं।

अदालतें अब ई-गवाही व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विशेषज्ञ साक्ष्य स्वीकार कर सकती हैं। विशेष रूप से 22 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा विकसित ई-साक्ष्य एप को अपनाया है, जिससे डिजिटल साक्ष्य को संग्रहीत और प्रस्तुत करना सरल हो गया है। ये परिवर्तन ई-कोर्ट्स परियोजना की बुनियाद पर निर्मित हुए हैं, जिसके तहत करीब 18,000 अदालतों का डिजिटलीकरण किया गया है।

सुधारों की दिशा में ठोस प्रगति हुई है, पर कुछ चुनौतियां भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की असमानता कई बार बाधा बनती है। फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं सीमित हैं और अदालतों तथा पुलिस स्टेशनों में कर्मचारियों की कमी भी एक गंभीर विषय है। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2022 के बीच साइबर अपराधों में 24.4 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो उच्च तकनीकी अपराधों से निपटने के लिए संस्थानों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दर्शाता है। बीएनएसएस के अंतर्गत गवाह संरक्षण नियमों को राज्य स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें पहचान छिपाने, स्थानांतरण और वीडियो गवाही की सुरक्षित व्यवस्था हो। प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक सुविधा के लिए मोबाइल और स्थायी, दोनों प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही, एक राष्ट्रीय डिजिटल अनुपालन डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, जो एफआईआर, जांच की प्रगति व रिमांड की प्रक्रिया पर निगरानी रखे। अंततः विधिक साक्षरता अभियान हो, जो नागरिकों को इसके बारे में जागरूक करे।

भारत के नए आपराधिक कानून एक सकारात्मक और सुविचारित बदलाव का प्रतीक हैं। प्रौद्योगिकी का समावेश, प्रक्रियात्मक सुधार और नागरिक अधिकारों पर केंद्रित दृष्टिकोण इस परिवर्तन को व्यावहारिक बनाते हैं। पहले वर्ष में एक मजबूत आधार स्थापित हो चुका है; अब जरूरत इन्हें और मजबूती से आगे बढ़ाने की है। यदि यह यात्रा प्रशिक्षण, निवेश और नीति समर्थन से सशक्त की जाए, तो भारत की न्याय प्रणाली वास्तव में अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बन सकती है।

-साथ में अक्षिता गुप्ता, शोध छात्रा (विधि)।
edit@amarujala.com

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 1 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

हर समय मुस्कराते रहना, चित्त शान्त रहना, उद्विग्नता और भटकाव का न होना, स्पष्ट विचार, स्पष्ट धारणा और स्पष्ट निर्णय, धीर पुरुषों और योगियों के लक्षण है

-भगवान श्री कृष्ण

हिन्दी पर सियासी संग्राम

महाराष्ट्र के विद्यालयों में पहली कक्षा से हिन्दी भाषा को शामिल करने के खिलाफ बढ़ते विरोध के दरम्यान मंत्रिमंडल ने त्रि-भाषा नीति पर सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। भाषा नीति के कार्यान्वयन व आगे की राह सुझाने के लिए शिक्षाविद् की अध्यक्षता में समिति का गठन करने की घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने की। राज्य सरकार ने अप्रैल मध्य में आदेश जारी किया था कि अंग्रेजी व मराठी माध्यम स्कूलों के छात्रों के लिए पहली से पांचवीं कक्षा तक हिन्दी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया था, परंतु जबरदस्त विरोध के चलते महीने भर बाद ही संशोधित सरकारी आदेश द्वारा हिन्दी को वैकल्पिक विषय बता दिया गया। आदेश को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री ने दलीलें दीं, कि मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे द्वारा कक्षा एक से बारह तक तीन भाषा नीति

लागू करने की सिफारिशें स्वीकारी थीं व कार्यान्वयन पर सामिति गठित की थीं। भाषा विवाद देश में नया नहीं है। दक्षिण के कई राज्य हिन्दी का सिर्फ विरोध ही नहीं करते रहे हैं बल्कि इसे थोपे जाने के आरोप भी मढ़ते रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रि-भाषा लागू करने की बात की गई है। जिसमें कम-से-कम दो भाषाएं भारत की मूल होनी अनिवार्य है। तीसरी भाषा का चयन छात्र/राज्य व क्षेत्र के अनुरूप करने की बात की गई। मगर स्थानीय राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाया और वे पूर्वाग्रह से हिन्दी थोपने का विरोध करने में जुट गए। बेशक राज्यों में सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों से स्थानीय भाषा के ज्ञान की अनिवार्यता अभी भी है। महाराष्ट्र में बहुसंख्य लोग मराठी बोलते हैं। यह देश में प्रयोग की जाते वाली भाषाओं में तीसरा स्थान रखती है, जिसे पश्चिम भारत के अन्य राज्यों में भी खूब प्रयोग किया जाता है। बावजूद इसके भाषा विवाद में जबरन हिन्दी को घसीटना सिर्फ राजनीतिक कीचड़ उछालने का दस्तूर बन गया है, जिस पर सरकार को कड़ा निर्णय लेना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय नीति को लेकर राज्यों को सहिष्णुता बरतनी चाहिए। केंद्र को इस पर दखलंदाजी करने पर संकोच नहीं करना चाहिए। जब तीसरी भाषा का चुनाव छात्रों के इख्तियार में है, वे स्वेच्छापूर्वक न चाहें तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार का इस तरह का ढुलमुल रवैया उचित नहीं। अंग्रेजी पर बढ़ती निर्भरता और जरूरत को सहजतापूर्वक स्वीकारने वालों को एकता व अखंडता का सम्मान करते हुए जनता को यह इख्तियार देना होगा। भाषाओं की अपनी गरिमा व सम्मान है, उसके प्रति द्वेष कतई उचित नहीं है।

एमएसएमई की मजबूती

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्त्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही जमीनी स्तर पर नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं। एमएसएमई दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के सतत आर्थिक विकास के मद्देनजर एमएसएमई के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम अनिवार्य है। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि केंद्र सरकार ने इस अनिवार्यता को समझते हुए कई नीतिगत पहल की है। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन, ऋण की उपलब्धता में वृद्धि, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक के उद्यमों को अपनी वार्षिक खरीद आवश्यकताओं का कम-से-कम 35 फीसद एमएसएमई उद्यमों से प्रापण करने के लिए प्रोत्साहन, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों के

कौशल विकास जैसी तमाम पहल ने एमएसएमई उद्यमों के लिए स्थितियां उत्साहजनक बनाई हैं। इन प्रयासों ने पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। साथ ही, उम्मीद जगी है कि इन पहल से देश के समावेशी विकास में एमएसएमई पहले से कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण निभाने में सक्षम और सफल हो सकेंगे। चूंकि ये उद्यम बनिस्बत कम पूंजी लागत पर अधिक रोजगार अवसरों का सृजन करते हैं, और वह भी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, इसलिए कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और विकास के विकेंद्रीकरण में अपनी उपयोगी भूमिका निभा सकते हैं। कहना न होगा कि इससे ये उद्यम समावेशी विकास का महत्वपूर्ण जरिया बन सकते हैं। जमीनी स्तर पर नवाचार में भी एमएसएमई उद्यमों की भूमिका को समझा गया है। महिलाओं को इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए तो समाज के सर्वांगीण विकास की में नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। बेशक, सरकार के स्तर पर तमाम प्रयास और पहल हो रही हैं, लेकिन इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह क्षेत्र अनके चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। वित्त की समस्या, कंपनियों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, नवीनतम प्रौद्योगिकी की कमी, कच्चे माल, सीमित बाजार, विलंबित भुगतान और कम कुशल कार्यबल आदि समस्याओं का निदान हो सका तो यकीनन यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में अपेक्षित योगदान देगा।

शिशु मातृ सुरक्षा/अली खान

भारत की वैश्विक पहचान

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट और यूनाइटेड नेशन्स इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टीमेशन यानी यूएन आईजीएमई की 2024 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि माताओं और शिशुओं को बचाने में भारत दुनिया में अव्वल साबित हो रहा है। भारत ने हाल के वर्षों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में जो गिरावट दर्ज की है, वह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की प्रतिबद्धता, दृढ़ नीति और सामाजिक जागरूकता की परिणति है। संयुक्त राष्ट्र की 2000 से 2023 तक की रिपोर्ट दर्शाती है कि इस अवधि में भारत ने करीब पांच लाख माताओं और 80 लाख नवजात शिशुओं की जान बचाई।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में शिशु मृत्यु दर में 59 फीसद, नवजात मृत्यु दर में 70 फीसद और शून्य डोज वाले बच्चों की मृत्यु दर में 78 फीसद की गिरावट आई है। जबकि वैश्विक औसत क्रमशः 51 फीसद, 54 फीसद और 61 फीसद रहा है। यह अंतर दर्शाता है कि भारत न केवल अपनी आंतरिक जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक औसत को पीछे छोड़ता जा रहा है। भारत ने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाकर न केवल अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य मंच पर एक प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। दरअसल, भारत ने टीकाकरण अभियान में जो मजबूती दिखाई, उसने पूरी तस्वीर बदल दी है। 2017 में शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष और बाद में उसका उन्नत संस्करण इंटेंस मिशन इंद्रधनुष, इस बदलाव के महत्त्वपूर्ण कारण रहे। दरअसल, शिशु-मातृ सुरक्षा में निवेश करने से देश को दीर्घकालिक लाभ मिलता है। एक स्वस्थ शिशु, एक सशक्त नागरिक की नींव है। एक सुरक्षित मां, एक सशक्त पीढ़ी की जननी है। जब हम एक नवजात को जीवन की शुरुआत में ही सुरक्षा देते हैं, तो वह भविष्य में बेहतर विद्यार्थी, कुशल श्रमिक, जागरूक नागरिक और सशक्त मानव संसाधन बनता है। अब आवश्यकता है इस सफलता को टिकाऊ बनाने की, ताकि हर मां और नवजात को जीवन की शुरुआत में ही वह सुरक्षा और सम्मान मिल सके, जिसका वे पूर्ण रूप से हकदार है।

देश का तानाशाही से सामना

आपातकाल

प्रह्लाद जोशी

25 जून, 1975 की मध्यरात्रि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया। इस निर्णय ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को 21 महीने तक चलने वाले सत्तावादी शासन के दौर में धकेल दिया, जिसके दौरान भारतीय राज्य ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, प्रेस की सेंसरशिप, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन और लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने का साक्षात्कार किया। यद्यपि आपातकाल 'आंतरिक अशांति' का हवाला देकर लगाया गया था, वास्तव में यह इंदिरा गांधी के अधिकार के प्रति राजनीतिक और न्यायिक चुनौतियों-विशेषकर चुनावी धांधलियों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा-का सीधा जवाब था।

किसी भी लोकतंत्र के केंद्र में उसकी संस्थाएं होती हैं-संसद, न्यायपालिका, प्रेस और स्वतंत्र वैधानिक निकाय। आपातकाल के दौरान, इन्हें व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया। संसद महज एक औपचारिक निकाय बनकर रह गई जो कार्यपालिका की इच्छा को मंजूरी देती थी। भारी बहुमत वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने बिना वास्तविक बहस के कठोर कानूनों और संशोधनों को पारित करवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया।

-न्यायपालिका को आज्ञाकारी बना दिया गया। सरकार ने न्यायिक नियुक्तियों में सक्रिय रूप से हेराफेरी की और विशेष रूप से प्रतिकूल फैसलों के जवाब में न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया या उन्हें दरकिनार किया। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना का अल्पमत-जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कि जीवन के अधिकार के निलंबन को भी बरकरार रखा-न्यायिक स्वतंत्रता का एक दुर्लभ प्रकाश स्तंभ था। प्रेस की स्वतंत्रता लगभग समाप्त कर दी गई। पूर्व-सेंसरशिप के आदेशों और कारावास की धमकियों के माध्यम से अखबारों का मुंह बंद कर दिया गया। विशेष रूप से, द इंडियन एक्सप्रेस ने इस सेंसरशिप के विरोध में एक मूक विरोध के रूप में खाली संपादकीय प्रकाशित किया।

-चुनाव आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं को स्वायत्तता से वंचित कर दिया गया और कार्यपालिका शक्ति को मजबूत करने के लिए उन्हें औजार बना दिया गया। आपातकाल का सबसे भयावह पहलू राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से मौलिक अधिकारों का निलंबन था। अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), 19 (भाषण और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा करने, संघ बनाने और आवागमन की स्वतंत्रता), 21 (जीवन और

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और 22 (मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण) या तो निलंबित कर दिए गए या निरर्थक बना दिए गए। कठोर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत रक्षा नियमावली के तहत, 1,00,000 से अधिक लोगों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया गया। अधिकांश राजनीतिक विरोधी, ट्रेड यूनियन नेता, छात्र नेता, पत्रकार और कार्यकर्ता थे। निवारक निरोध एक आदर्श बन गया, जिसका उपयोग असंतोष को कुचलने और भय पैदा करने के लिए किया गया। साथ ही, शहरी विकास और जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर :

-**जबरन नसबंदी अभियान**-जो काफी हद तक गरीबों को निशाना बनाते थे-इंदिरा के पुत्र संजय गांधी के निर्देशन में चलाए गए। बल और धमकी के तहत लाखों लोगों की नसबंदी कराई गई।

-दिल्ली के तुर्कमान गेट में झुग्गी विध्वंस के कारण मौतें और विस्थापन हुआ, जहां सुरक्षा बलों ने विरोध कर रहे निवासियों पर गोली चलाई। यद्यपि आपातकाल अधिकारों के निलंबन और बड़े पैमाने पर नजरबंदी के लिए जाना जाता है, कम स्वीकार किया गया-लेकिन गहराई से परेशान करने वाला-पहलू था विरोध को दबाने और राजनीतिक कैदियों के मनोबल को तोड़ने के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना का व्यापक इस्तेमाल। हजारों कार्यकर्ताओं, छात्रों और विपक्षी कार्यकर्ताओं को सिर्फ जेल में नहीं डाला गया-उन्हें हिरासत में बुनियादी मानवीय गरिमा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के स्पष्ट उल्लंघन में क्रूर और अपमानजनक व्यवहार का शिकार बनाया गया। सबसे भयानक विवरणों में लॉरेंस फर्नांडिस और सुरेश कुमार के हैं, दोनों राजनीतिक कार्यकर्ता और शासन के मुखर आलोचक थे। लॉरेंस फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस के भाई, समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और बड़ौदा डायनामाइट मामले में गिरफ्तार किए गए थे, जिसे राज्य के खिलाफ एक विध्वंसक साजिश के रूप में झूठा प्रचारित किया गया था। उन्हें यातनाएं दी गईं, बिजली के झटके दिए गए, लंबे समय तक एकांत कारावास में रखा गया।

यातना के बावजूद, लॉरेंस फर्नांडिस ने उन आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जो राजनीतिक रूप से प्रेरित और बेबुनियाद थे। सुरेश कुमार, एक युवा छात्र जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे, को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ कठोर और अमानवीय व्यवहार किया गया था। इसी प्रकार, भय पैदा करने के लिए अनगिनत व्यक्तियों को व्यवस्थित रूप से चिह्नित कर कठोर व्यवहार का शिकार बनाया गया। आपातकाल की घोषणा और उसे बनाए रखने के तरीके ने ही संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति बेपरवाही का बेशर्मीपूर्ण नमूना पेश किया। अनुच्छेद 352 के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करें। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने केवल इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देर रात घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे सामूहिक मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हुआ।

यह एकतरफाबाद कानूनों के पारित होने तक विस्तारित हुआ। सबसे जघन्य उदाहरण था 42वें संशोधन का पारित होना, जिसने संविधान को मूल रूप से कार्यपालिका के पक्ष में बदल दिया। 42वें संशोधन को पारित करने के लिए संसदीय समय में हेरफेर, आपातकाल की असंवैधानिक घोषणा, और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का व्यापक दमन-ये सभी लोकतांत्रिक शासन के पूर्ण पतन की ओर इशारा करते हैं। भारत आपातकाल से बच गया, लेकिन केवल कुछ बहादुर लोगों के लचीलेपन और इसके मतदाताओं के सामूहिक ज्ञान के कारण। यह एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में खड़ा है : स्वतंत्रता की कीमत चिरस्थायी सतर्कता है।

(लेखक केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं)

> आपातकाल की घोषणा और उसे बनाए रखने के तरीके ने ही संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति बेपरवाही का बेशर्मीपूर्ण नमूना पेश किया। अनुच्छेद 352 के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करें। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने केवल इंदिरा गांधी की सिफारिश पर देर रात घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे सामूहिक मंत्रिमंडलीय जिम्मेदारी के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन हुआ

जामुन-स्वाद और सेहत का बेजोड़ संगम

- जामुन खाने में रसीला और स्वादिष्ट होता है। जामुन पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में उगाया गया। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में मिलता है। आयुर्वेद में जामुन को विशेष स्थान प्राप्त है
- जामुन का वैज्ञानिक नाम 'सिजीगियम क्यूमिनी' है। यह स्वाद में खट्टा-मीठा होता है, जिसे आम तौर पर नमक के साथ खाते हैं
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित रिपोर्ट (अक्टूबर, 2022) में बताया गया है कि जामुन को डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसी समस्याओं के इलाज में खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है
- सुश्रुत संहिता के अनुसार, जामुन में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन में सहायता करता है। इसकी गुठलियों से तैयार चूर्ण का सेवन करने वाले शुगर के मरीजों को काफी राहत पहुंचती है

(मीडिया इनपुट्स)

Special Intensive Revision

चुनाव आयोग का आदेश-अभूतपूर्व, अजीव, अलोकतांत्रिक और असंभव! बिहार में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं से ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो करोड़ों के पास नहीं होंगे। ये वोटर लिस्ट सुधार नहीं, वोट उड़ाने का खेल बन सकता है।

योगेंद्र यादव, राजनीतिक कार्यकर्ता
@_YogendraYadav

वैश्विक भारत की सशक्त प्रस्तुति

मोदी की विदेश यात्रा **डॉ. एस.पी. शाही**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 से 9 जुलाई, 2025 तक की अपनी विदेश यात्रा के दौरान घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। यह यात्रा रणनीतिक कूटनीतिक अभियान है, जो भारत के वैश्विक दृष्टिकोण, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, बहुपक्षीय नेतृत्व और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूती देने की दिशा में निर्णायक कदम है। यह दौरा न केवल इन देशों के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊर्जा देगा, बल्कि भारत की बहुपक्षीय उपस्थिति को वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त करेगा।

घाना (2-3 जुलाई, 2025): अफ्रीकी साझेदारी का नया अध्याय

प्रधानमंत्री मोदी की यह घाना यात्रा उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। लगभग तीन दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली घाना यात्रा होगी। यह यात्रा बताती है कि भारत अब अफ्रीकी देशों के साथ अपने रिश्तों को केवल ऐतिहासिक भाईचारे की भावना से नहीं, बल्कि सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी देख रहा है।

त्रिनिदाद और टोबैगो (3-4 जुलाई, 2025): सांस्कृतिक रिश्तों को राजनीतिक सुदृढ़ता

त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की प्रधानमंत्री बिहार मूल की कमला परसाद-बिसेसर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इस देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1999 के बाद पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और विश्व मंच पर इसकी विचारधारा की प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करेगा। भारत और के बीच सांस्कृतिक और जन-जन के स्तर पर जो संबंध हैं, वह इस यात्रा का मूल आधार हैं।

अर्जेंटीना (4-5 जुलाई, 2025): रणनीतिक भागीदारी का विस्तार

प्रधानमंत्री अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह यात्रा भारत और अर्जेंटीना के बीच रणनीतिक भागीदारी को बहुआयामी स्वरूप देने का प्रयास है। रक्षा, कृषि, खनन, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग

की समीक्षा और विस्तार यात्रा का केंद्र होगा।

ब्राजील (5-8 जुलाई, 2025): वैश्विक नेतृत्व में भारत की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा के निमंत्रण पर ब्राजील की यात्रा पर होंगे। यहां वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिक्स के संदर्भ में भारत की भूमिका को वैश्विक मंच पर उभारने का अवसर प्रदान करेगी। रियो डी जेनेरियो में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन में सुधार, बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति लूला के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे।

नामीबिया (9 जुलाई, 2025): ऐतिहासिक संबंधों की पुनर्स्थापना

यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. नेटुम्बो नंदी-नदैतवा के निमंत्रण पर नामीबिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री न केवल राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, बल्कि नामीबिया के संस्थापक पिता डॉ. सैम नुजोमा को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। यह यात्रा भारत और नामीबिया के गहरे और बहुआयामी ऐतिहासिक संबंधों की पुष्टि करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी की यह बहुपक्षीय यात्रा भारत की विदेश नीति की नवीन सोच, व्यापक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर कूटनीति का उदाहरण है। यह केवल समझौतों और घोषणाओं की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की वैश्विक जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक मूल्य, और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। यह यात्रा दक्षिण-दक्षिण सहयोग, वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच पारस्परिकता, और भारत की एक सॉफ्ट पावर के साथ-साथ हार्ड पावर के रूप में बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति उन देशों में हो रही है जहां भारत के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक जुड़ाव की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। 2 से 9 जुलाई, 2025 की यह यात्रा निस्संदेह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कूटनीतिक क्षण है, जो आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक नीति, आर्थिक विस्तार और सांस्कृतिक नेतृत्व को मजबूती देगा।

(लेखक मगध विवि के कुलपति और राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं। लेख में विचार निजी हैं)

लड़ो मत वासना से — ओशो

झेन फकीरों की कथा है : एक बूढ़ा फकीर और एक युवक फकीर आश्रम वापस लौट रहे हैं। छोटी-सी नदी पड़ती है। और एक सुंदर युवती नदी पार करने को खड़ी है, लेकिन डरती है। अनजानी नदी है, पहाड़ी नदी है, गहरी हो, खतरनाक हो, बड़ी तेज धार है। बूढ़ा संन्यासी तो नीचे आंख करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि यह पार होना चाहती है, हाथ का सहारा मांगती है, लेकिन वह डर जाता है। हाथ का सहारा! इस बात में पड़ना ठीक नहीं! लेकिन युवक संन्यासी उसके पीछे ही चला आ रहा है। वह युवती से पूछता है कि क्या कारण है। सांझ हुई जा रही है, जल्दी ही सूरज डूब जाएगा और युवती अकेली छूट जाएगी। युवती कहती है : मैं बहुत डरी हुई हूं। पानी में उतरते घबराती हूं। मुझे उस पार जाना है। तो वह युवक संन्यासी उसे कंधे पर ले लेता है। बूढ़ा संन्यासी उस पार पहुंच गया, तब उसे याद आती है कि मेरे पीछे एक युवा संन्यासी भी आ रहा है, कहीं वह इस झंझट में न पड़ जाए! लौटकर देखता है तो उसकी आंखों को भरोसा ही नहीं आता है : वह कंधे पर बिठाए हुए लड़की को नदी पार कर रहा है! बूढ़ा तो आग से जल-भुन गया। युवक संन्यासी ने युवती को दूसरे किनारे उतार दिया, फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। दो मील तक कोई बात न हुई। दो मील बाद बूढ़े को बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने कहा, यह ठीक नहीं हुआ और मुझे गुरु को जाकर कहना ही पड़ेगा; नियम का उल्लंघन हुआ है। तुमने उस सुंदर युवती को कंधे पर क्यों बिठाया! युवक ने कहा, 'आप बहुत थक गए होंगे। मैं तो युवती को नदी के तट पर ही उतार आया; आप अभी कंधे पर बिठाए हुए हैं! आप बहुत थक गए होंगे! बात आई और गई भी हो गई, अभी तक आप भूले नहीं!' जिसको तुम महात्मा कहते हो, वह आंख तो झुका लेगा; लेकिन आंख झुकाने से कहीं वासनाएं समाप्त होती हैं! आंख फोड़ भी लो तो भी वासनाएं समाप्त नहीं होती। वासनाओं का आंखों से क्या संबंध है? क्या तुम सोचते हो, अंधे को वासना नहीं होती? अंधे को इतनी ही वासना होती है, जितनी तुमको। क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास, उपाय भी नहीं; असहाय है। उसके भीतर भी प्रबल आकांक्षा है। तो आंख बंद कर लेने से क्या होगा? किसे धोखा दे रहे हो? तो एक तो साधारण आदमी है, जिसके शरीर में ज्वर उठता है वासना का, सौंदर्य को देखकर।

रीडर्स मेल

संकट में मध्यम वर्ग

आंकड़ों की बुनियाद पर यह बात सामने आती है कि मध्यम वर्ग की आय में जो वृद्धि हो रही है, वह न केवल असमान है, बल्कि मुद्रास्फीति से समायोजित करने पर नगण्य रह जाती है। आंकड़ों के अनुसार, शहरी मध्यवर्गीय परिवारों की औसत मासिक आय 2020 में जहाँ 31,500 ₹ थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर केवल 34,000 ₹ के आसपास पहुँची है। लेकिन इसी अवधि में आवश्यक वस्तुओं, जैसे भोजन, शिक्षा, चिकित्सा और किराए की लागत में 2540% की वृद्धि हुई है। यानी वास्तविक क्रय शक्ति घटी है, जिससे उपभोग में स्वाभाविक संकोच आया है। मध्यम वर्ग अब 'आवश्यक' बनाम 'विलासिता' की वस्तुओं के बीच चयन कर रहा है। एक ओर सरकार पूंजीगत निवेश बढ़ा रही है, परंतु निजी उपभोग की ठहराव की स्थिति समग्र मांग पर ब्रेक लगा रही है। यदि यह प्रवृत्ति बनी रही, तो न केवल उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि कर संग्रह और सामाजिक गतिशीलता पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

अवनीश कुमार गुप्ता, ई मेल से

सख्त कदम उठाएं ममता

जिस तरह से आए दिन बलात्कार और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे हम पुरुषों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामला अभी हमारे मानसिक पटल पर जीवित है और यह दर्दनाक घटना फिर हो गई कोलकाता में; जहां विधि महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की छात्रा का बलात्कार उसी के सीनियर ने किया और दो और लड़कों ने उसकी फिल्म बनाई। इस मामले में सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि इस घटना के आरोपी की निंदा करने की बजाय 2 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित लड़की पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी को ठोस कदम उठाने की जरूरत है वरना कोलकाता की छवि पर बट्टा लगता जाएगा।

बाल गोविंद, नोएडा

घुटने पर कनाडा

डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने कनाडा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। रविवार देर रात कनाडा ने डिजिटल सर्विस टैक्स (डीएसटी) रद्द कर दिया, जो सोमवार से अमेरिकी टेक दिग्गजों पर 3 फीसद कर लगाने वाला था। ट्रंप ने इसे 'अमेरिका पर हमला' करार देते हुए कठोर टैरिफ और व्यापार वार्ता तोड़ने की चेतावनी दी थी। कनाडाई वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ट्रंप 21 जुलाई तक नये व्यापार समझौते के लिए वार्ता फिर शुरू करेंगे। वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन डीएसटी अधिनियम रद्द करने हेतु विधेयक पेश करेंगे। 2020 में शुरू हुआ डिजिटल सर्विस टैक्स, गूगल, अमेजन जैसी कंपनियों से कनाडाई राजस्व पर कर वसूलने का कदम था। कनाडा का लक्ष्य वैश्विक कर समझौता रहा, पर ट्रंप की दबाव रणनीति ने इसे पटरी से उतार दिया। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने का अवसर हो सकता है, बशर्ते वार्ता सफल हों। कनाडा का यह पीछे हटना ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स की जीत है या रणनीतिक चाल? समय बताएगा।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 313
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, [illegible], 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - स्नेहा मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
[illegible] UP/BR/GZB-38/2024-2026

हिन्दुस्तान
1936
सत्य · सार्थक · सटीक

हिंदी फिर निशाने पर

त्रिभाषा नीति को महाराष्ट्र में लगा झटका दुखद और अफसोसजनक है। राजनीतिक दबाव के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घोषणा करनी पड़ी कि सरकार ने अप्रैल व जून में जारी किए गए प्रस्तावों को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। दुर्भाग्य, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब, महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी मंजूर नहीं है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया था कि सरकारी प्रयासों के हाथ-पांव फूलने लगे थे। ठाकरे बंधुओं का आंदोलन दिनोंदिन उग्र होता जा रहा था। यह सच है, हर राज्य के लिए भाषा की राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुंह नहीं मोड़ सकती। वैसे भारत में भाषा की राजनीति नई नहीं है। जब से राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है, भाषा तभी से राजनीति का एक प्रिय विषय रही है।

अब एक तरफ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिक्षाविद् डॉ नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में भाषा नीति के क्रियान्वयन और आगे की राह पर सुझाव देने के लिए एक समिति की घोषणा की है। दूसरी तरफ, भाषा के मोर्चे पर अपनी सफलता से उत्साहित ठाकरे बंधु विशाल प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। जाहिर है, यह बताने की कोशिश होगी कि हिंदी को थोपा नहीं जा सकता। यह बात अलग है कि एक समिति ने जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी, तब उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब हिंदी का मामला बड़ा नहीं था, पर आज जब ठाकरे विपक्ष में हैं, तब यही मुद्दा सबसे अहम हो गया है। भाषा की राजनीति में सत्ता पक्ष कमजोर पाया गया है, जबकि विपक्षी दल श्रेय लेने से पीछे नहीं हटने वाले। विडंबना देखिए, एक समिति ने हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी और अब दूसरी समिति इस सिफारिश का अध्ययन करेगी। कहीं मामला माशेलकर समिति बनाम जाधव समिति न बन जाए? हालांकि, जिस तरह की त्रासद भाषा-राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, उससे यही लगता है कि समिति में बैठने वाले विशेषज्ञों की राय को किनारे कर दिया जाएगा और राष्ट्रीयता पर क्षेत्रीयता की जीत हो जाएगी।

यह बहुत शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है।

ध्यान रहे, हिंदी के पक्ष में 16 अप्रैल को जारी प्रस्ताव को विरोध के चलते 17 जून को संशोधित कर दिया गया था। प्रावधान को उदार बना दिया गया था कि अगर किसी कक्षा में 20 से ज्यादा छात्र हिंदी पढ़ना नहीं चाहेंगे, तो वहां हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। अफसोस, यह प्रावधान भी क्षेत्रीय नेताओं को पसंद नहीं आया। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि सरकार मराठी मानुष की शक्ति से हार गई, पर वह इस बात को छिपा जा रहे हैं कि हारी तो वह हिंदी है, जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है। कहना चाहिए कि मराठा राजनीति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम तमिलनाडु को ही हिंदी विरोध के लिए जानते थे, पर इधर तीखे हिंदी विरोध में कर्नाटक के साथ ही, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। कहना ही होगा कि हिंदी समाज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। अपनी राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को इतना बल देना पड़ेगा कि कम से कम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अहिंदीभाषी राज्यों में स्वीकार किया जाए। क्या हिंदी प्रदेश के नेता इससे सबक लेंगे?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 01 जुलाई, 1950

वन महोत्सव

भारत के खाद्य और कृषि मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी की अपील पर देश भर में आज से वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह में नये वृक्ष उगाने का कार्य किया जायेगा। नये वृक्ष उगाने का आन्दोलन पुराना है, किन्तु श्री मुन्शी ने उसमें नये जीवन का संचार कर दिया है। उनकी नये वृक्ष उगाने की अपील का सारे देश से आशातीत उत्तर मिला है। उन्होंने एक करोड़ नये वृक्ष लगाने का लक्ष्य देश के सामने रखा था, किन्तु प्राप्त समाचारों से अनुमान होता है कि नये सिरे से लगाये जाने वाले वृक्षों की संख्या दो करोड़ तक पहुंच जायेगी। सभी राज्य सरकारों, सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक संस्थाओं, जिला बोर्डों ने 'वृक्ष उगाओ' आन्दोलन में योग देने का निर्णय किया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लगाकर प्रायः सभी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति इस आन्दोलन में भाग लेंगे। उनका उदाहरण आम लोगों को प्रेरणा देने वाला साबित होगा और देश भर में उसका व्यापक अनुसरण किया जायेगा।

श्री मुन्शी कल्पनाशील मानस के धनी हैं। उन्होंने 'वृक्ष उगाओ' आन्दोलन का संबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उस युग से जोड़ दिया है, जबकि मनुष्य जीवन के सर्वोच्च सत्यों की खोज के लिए वनों में जाकर रहता था और वहां के पेड़-पौधों से अपनी संतान की भांति प्यार करता था। वृक्षों के प्रति उसी ममता और कोमल भावनाओं के विकास की आवश्यकता है जिसका परिचय शकुंतला ने कण्व ऋषि के आश्रम में दिया था। हमारे प्राचीन ग्रंथ वृक्षों की महिमा से भरे हुए हैं। वृक्षों की शीतल छाया का सुख और आनन्द वह यात्री बता सकता है, जो कठिन यात्रा के बाद अपनी थकान उसके नीचे बैठकर दूर करता है। मनुष्य जब अपने आस-पास के शुष्क वातावरण से वृक्षों की हरी-भरी गोदी में पहुंच जाता है, तो वह स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करता है। उसका मन प्रसन्नता से नाच उठता है। वृक्षों के प्रति मनुष्य का यह आकर्षण एकदम स्वाभाविक है। वनों की पुकार को जब से मनुष्य भूल गया और वृक्षों की ओर उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगा, तभी से उसके जीवन में आनन्द का स्रोत सूख गया और वह भारवाही जीवन बिता रहा है। वृक्षों का मनुष्य जीवन के लिए जो महत्व है, वह कपोल-कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, उसका वैज्ञानिक आधार भी है। वृक्ष समय पर वर्षा में सहायक होते हैं।

महिलाएं भी उठाने लगीं क्रूर कदम

राय की राय

यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

आखिर क्यों उठाया होगा सोनम ने दुर्लभतम क्रूरता से भरा वह कदम? पिछले कुछ दिनों से देश में स्त्रियों की ओर से हिंसक पहल की बाढ़ सी आई हुई है।

पिछले दिनों भारत में अपराध शास्त्र से जुड़े कई मिथक टूटे हैं। सबसे पहले तो यह समझ गड़बड़ा गई है कि दांपत्य या पारिवारिक हिंसा पर पुरुषों का ही एकाधिकार है और स्त्रियां हमेशा उसका शिकार होती हैं। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े ही इस सरलीकृत समझ की धज्जियां उड़ा देने के लिए काफी हैं। स्त्रियों ने न सिर्फ जघन्यतम हत्याओं के लिए भाड़े के हत्यारों का इंतजाम किया, बल्कि कई मामलों में तो उन्होंने हत्या की वारदात में नेतृत्वकारी भूमिका भी निभाई।

स्त्री का यह चेहरा हमारी पारंपरिक चेतना को किस कदर झकझोर सकता है, इसे समझने के लिए पिछले दिनों शिलांग (मेघालय) में हनीमून मनाने गए दंपति में पति राजा रघुवंशी की हत्या और इस कांड में पत्नी सोनम की संलिप्तता की खबर को देखना ही पर्याप्त होगा। एक पुरुष हत्यारे को आम तौर से जितनी 'ख्याति' मिलती है, उससे हजार गुना अधिक चर्चा हत्या में शरीक किसी महिला को मिल सकती है। इंदौर की सोनम के हिस्से में भी टीआरपी की चाहत वाले मीडिया की उदारता खूब आई। इंदौर से गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे सोनम और उसके प्रेमी या पति को लेकर जिस तरह के चटखारे लिए गए, उससे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर एक गंभीर समाजशास्त्रीय बहस होते-होते रह गई।

क्यों उठाया होगा सोनम ने दुर्लभतम क्रूरता से भरा यह कदम? सनसनीखेज मीडिया जिसकी बेवफाई के किस्से चुस्कियां ले लेकर सुना रहा है, क्या उसका आचरण भिन्न नहीं होता, अगर उसे एक अनचाहे रिश्ते में न धकेल दिया गया होता? सोनम उन असंख्य भारतीय लड़कियों में से एक है, जिन्हें भावनात्मक रूप से शोषित कर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक गठबंधन में बांध दिया जाता है, जिसके साथ उनका पूरा जीवन नर्क बनकर रह जाता है। मां-बाप मानकर चलते हैं कि एक बार शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी को राजी करने के लिए वे किसी हद तक जा सकते हैं। धमकाना, बहलाना-फुसलाना या भावनात्मक ब्लैकमेल जैसा कुछ भी हो सकता है। सोनम के साथ भी यही सब कुछ हुआ।

पिछले कुछ दिनों से स्त्रियों की ओर से हिंसात्मक पहल की बाढ़ सी आई हुई है। यह भी हो सकता है कि इन घटनाओं को ढकने की प्रवृत्ति कम हुई है और सोशल मीडिया ने इन सूचनाओं तक हमारी पहुंच इतनी सहज बना दी है कि मुख्यधारा की पत्रकारिता के लिए उसकी उपेक्षा संभव नहीं रह गई। पर इस शोर-शराबे के बीच वह तथ्य उपेक्षित रह गया है, जिसका ऊपर जिक्र आया है और जिससे एक महत्वपूर्ण विमर्श खड़ा हो सकता था।

हमें इस तथ्य से चिंतित होना चाहिए कि हमारे देश में प्रेम के लिए स्थान सिकुड़ता जा रहा है। किसी भी दिन के अखबार में छपी हिंसा की घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें अधिकांश यौन हिंसा की हैं। पार्कों, सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी लड़के और लड़की की उपस्थिति इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई सिरफिरा व्यक्ति या समूह उन्हें असहज महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर देगा। वैलेंटाइन डे पर हिंदू धर्म के रखवाले उन्हें पार्कों में तलाशते हैं, तो मेरठ के आस-पास बुर्कानशीं किसी लड़की को इस बात के लिए सरेराह रोककर अपमानित किया जा सकता है कि वह किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही है।

कुछ चैनलों पर तर्क दिया गया कि यदि सोनम तैयार नहीं होती, तो कैसे उसका परिवार जबरदस्ती उसकी शादी करा पाता? एक पैनलिस्ट ने, जो खुद कानून के विद्वान थे, बड़े दंभ से कहा कि हमारे देश में संविधान है, अदालतें हैं और सोनम को ही कठघरे में खड़ा कर पूछा कि वह किसी अदालत में क्यों नहीं गई? वह भूल गए कि अदालतों तक पहुंचना एक भारतीय नागरिक के लिए किस कदर मुश्किल है! अदालतें भी सामान्यतया प्रचलित सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होती हैं। हाल में उत्तर भारत के दो उच्च न्यायालयों ने प्रेमी जोड़ों को यह कहकर सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया कि उनका कृत्य समाज में अराजकता फैलाएगा। एक राज्य ने कानून में यहां तक परिवर्तन कर दिया है कि अब प्रेमी जोड़ों को सिविल विवाह रजिस्टर कराने के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी, यानी एक छोटी सी खिड़की जो संविधान ने खोल रखी थी, उसे भी बंद कर दिया गया। कुछ राज्यों में लिव-इन रिलेशनशिप को बड़े अपमानजनक ढंग से पंजीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह भी तब, जब सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे रिश्तों को संविधान-सम्मत घोषित कर रखा है।

यदि सोनम प्रकरण पर कोई गंभीर विमर्श होता, तो इस पर भी चर्चा हुई होती कि हमारे समाज में लड़कों को ऐसी परवरिश क्यों नहीं दी जा रही कि वे लैंगिक समानता में विश्वास रखने लगें। किसी भारतीय लड़की के लिए यह आम सा अनुभव है कि वर्षों तक भावनात्मक और शारीरिक शोषण करने के बाद कोई लड़का यह घोषित कर दे कि विवाह तो वह मां-बाप की मर्जी के मुताबिक ही करेगा। स्वाभाविक है, इस मर्जी में जाति या दहेज की भूमिका भी होगी। एक औसत भारतीय नौजवान/नवयुवती को हम निर्णय का अधिकार देना बड़ा खतरनाक समझते हैं। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं, जिनमें सजातीय विवाह के प्रसंग में भी अभिभावकों ने इस बात पर अड़ंगा लगाया कि बिना उनकी मर्जी के किसी जोड़े ने प्रेम करने का दुस्साहस कैसे कर डाला?

जिस समय हिंदू कोड बिल आकार ले रहा था, विवाह एक पवित्र मूल्य की तरह था और जिसमें एक बार बंध जाने के बाद उससे निकल पाना लगभग असंभव बना दिया गया था। एक कहावत की तरह दोहराया जाता रहा कि जिस घर में डोली जाती है, वहीं से अर्थी निकलनी चाहिए। विवाह सात जन्मों का बंधन होता है। अब इन मूल्यों का कोई मतलब नहीं रह गया है। किसी हिंदू पत्नी या पति के लिए तलाक हासिल करना एक समय-साध्य, खर्चीला और उबाऊ दुःस्वप्न की तरह है। परिणाम किसी एक भागीदार की हत्या तक पहुंच सकता है। क्या अब समय नहीं आ गया कि हम अनचाहे रिश्तों को आसानी से समाप्त करने के बारे में सोचें?

घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच हमें अपने समाज में प्रेम के लिए स्पेस बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। प्रेम के बिना स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न समाज नहीं बनाया जा सकता।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जब नदियां अविरल बहेंगी, तभी जलभराव थमेगा

यहां स्कैन करें

पंकज चतुर्वेदी | वरिष्ठ पत्रकार

बीते डेढ़ महीने में दिल्ली में कुल चार बार ठीक-ठाक बादल बरसे और बमुश्किल एक घंटे की बरसात में ही राष्ट्रीय राजधानी ठिठक सी गई। तीन दशकों से सरकारों के लाख दावों के बावजूद हर साल देश में जलभराव वाले शहरों और जगहों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालिया आंकड़ों पर गौर करें, तो अकेली दिल्ली में साल 2023 में जहां जलभराव के 308 बिंदु चिह्नित किए गए थे, 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 410 हो गई है। अब तो डूबने का दायरा अतिविशिष्ट कहलाने वाली लुटियन दिल्ली तक बढ़ गया है।

पानी भरते ही दो कारण सबसे पहले गिनाए जाते हैं- एक, इस महीने या इतने कम समय में इतना अधिक पानी कितने वर्षों के बाद बरसा और दूसरा, नालियों की सफाई न होना या सीवर तंत्र का पुराना पड़ जाना। याद रखिए, दिल्ली बसी ही इसलिए थी कि यहां से यमुना बह रही थी। इसके जलभराव या फिर इसकी प्यास का एकमात्र इलाज यमुना ही है। हमारे पुरखों ने दिल्ली के हर कोने से जमा जल को यमुना या फिर तालाबों तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी, जिसे आधुनिक तंत्र ने उजाड़ दिया। लिहाजा, जलभराव की समस्या का निदान पारंपरिक ज्ञान को फिर से महत्व देने में है।

वैसे, मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं है। थोड़ा सा पानी बरसते ही दिल्ली से सटे शहर भी ठिठक जाते हैं। पिछली चार बारिशों में इन शहरों की सड़कें भी दरिया बन गईं और नाले उफन आए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों के नामचीन इलाके घुटने-घुटने पानी में डूबे दिखे। उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे हापुड़-खुर्जा हों या हरियाणा का पलवल, सभी पानी-पानी हो गए। ऐसी ही खबरें गोंडा, औरैया, पटना और देहरादून से आ रही हैं। स्मार्ट सिटी घोषित हो गए गोवा की राजधानी पणजी में तो पहली बरसात में ही शहर में तीन-तीन फुट पानी था।

दरअसल, शहरी नियोजन के लिए गठित लंबे-चौड़े सरकारी अमले पानी के जमाव के कारण शहरों के ठहर जाने पर खुद को असहाय पाते हैं। सारा दोष नालों की सफाई न होने, बढ़ती आबादी, घटते संसाधनों और पर्यावरण से छेड़छाड़ पर थोप देते हैं। वैसे, इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाता कि इन नालों की सफाई साल भर क्यों नहीं होती और इसके लिए मई-जून का इंतजार क्यों किया जाता है? यह सभी जानते हैं कि दिल्ली में बने ढेर सारे पुलों के निचले सिरे, अंडरपास और सब-वे हल्की बारिश में भी जलभराव के शिकार हो जाते हैं, पर कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि इनके निर्माण या रखरखाव की वह कौन-सी कमी है?

यह पूरे देश में हुआ है कि जिन जल-तिजोरियों को बरसात की हरेक बूंद को सहेजने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, उसे 'रियल एस्टेट' मान लिया गया और कुदरत की नियामत के बरसते ही, बेपानी शहरों की सड़कें, कॉलोनियां पानी से लबालब हो जाती हैं। काश, शहरों की नदियों को अविरल बहने दिया गया होता। उनसे जुड़े तालाबों व नहरों को जीवन दे दिया जाए, तो दिल्ली हो या रांची, इनसे दोगुने बड़े शहरों को पानी देने और बारिश के चरम पर भी हर बूंद को अपने में समेट लेने की क्षमता इनमें है। नदी किनारे बसे शहरों में जलभराव का एक बड़ा कारण गाद और कचरे के कारण नदी का उथला हो जाना है। नदी की जल-ग्रहण क्षमता को कम करने में बड़ी मात्रा में जमा गाद (सिल्ट), रेत, सीवरेज, पूजा-पाठ की सामग्री, मलबा और तमाम तरह के कचरे का योगदान है। जब बड़े नाले गाद से बजबजाते हैं, तो शहरों पर जलभराव की चोट दोहरी होती है- चूंकि नाले का पानी नदी की तरफ लपकता है और उथली नदी में पहले से ही नाले के मुंह तक पानी भरा होता है, इसलिए नदी के प्रवाह से उपजे प्रतिगामी बल से नाले फिर पलटकर सड़कों को दरिया बना देते हैं।

दिल्ली और देश के तमाम बड़े शहरों को जलभराव से बचना है, तो उनको अपनी नदियों की गाद-सफाई भी सुनिश्चित करनी होगी।

जान लें, यदि दिल्ली या देश के तमाम बड़े शहरों को जलभराव की समस्या से बचना है, तो उनको सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नदियां अविरल बहें और उनकी गहराई व पाट बचे रहें। जलभराव पूरी तरह से मानवजन्य समस्या है। इसका निदान दूरगामी योजनाओं से ही संभव है; यह बात हमारे शहरी नियोजनकर्ताओं को भली-भांति समझनी पड़ेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

क्या वह कल आएगा

शरीर को भला-चंगा रखने की इच्छा से लोग योग सीखने आते हैं। कुछ लोग सुबह-सुबह टहलने की कोशिश करते हैं। कुछ दूसरे व्यायामों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन, यदि गौर करें कि क्या ये लोग सीखे हुए योगासन या व्यायामों को नियमित रूप से करते हैं, तो आप यही पाएंगे कि नहीं करते। उन्हीं से पूछकर देखिए, फट से जवाब मिलेगा, 'आज बड़ी थकान है। कल से मैं बिना नागा करूंगा।'

क्या कल से ये लोग टहलने जाएंगे? नियमित रूप से व्यायाम करेंगे? कोई गारंटी नहीं। आप अपनी पसंद का काम किए बिना सुस्ती से बैठेंगे, तो खुद आपका मन अपराध-बोध के साथ आपको डांटेगा, 'यह क्या? सुस्त बैठे हो? उठो।' आपका अहंकार कभी भी आपको यह स्वीकार करने नहीं देगा कि 'मैं गैर-जिम्मेदार हूं।' आपका अहंकार यही तसल्ली देकर मन को धोखे में रखेगा कि मैं आलसी नहीं हूं भई, कल से शुरू करने वाला हूं।

कर्नाटक के कुछ गांवों में एक अंधविश्वास है। वहां के लोग मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद उस इलाके के भूत-प्रेत घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। लोगों को इस बात का भी डर है कि इन भूत-प्रेतों को भगाने की कोशिश की गई, तो वे गुस्सैल हो जाएंगे, फिर उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसलिए उन गांवों के लोगों ने एक युक्ति लगा रखी है। चूंकि मान्यता है कि भूत-प्रेतों को लाल रंग पसंद आता है, इसलिए उसी रंग में हरेक घर के दरवाजे पर लिख देते हैं- 'कल आओ।' कारण पूछें, तो लोग कहते हैं, भूत-प्रेत जब भी आएं, यह सूचना देखकर वापस चले जाएंगे।'

किसी काम को आज या अभी करने को कहा जाए, तो उसे फौरन करने की जरूरत पड़ती है। कल एक अनागत दिन होता है, कभी न आने वाला दिन। इसलिए यदि आप अपने स्वास्थ्य से, कामयाबी से, आनंद से, अपने जीवन की जरूरतों से कहेंगे कि कल आओ, तो वे खुशी से चले जाएंगे। सावधान रहिए। 'कल से...' जुमला मन के अंदर गहराई से जमी हुई चालाकी है। जीवन के कई चरणों पर आपने इस मायावी चालाकी को शह दे रखी है। जो काम करने लायक है, उसे किए

हम जिसे कल कहते हैं, उससे हमारा सामना होने वाला नहीं है। वह जब आज बनता है, तभी हम उसका सामना करते हैं। कल नामक समय हमारे अनुभव में साकार होने वाला नहीं है।

बिना टालने वाले लोगों के लिए सदा ही कल शुभ दिन होता है। 'कल करेंगे' कह देने पर जिम्मेदारी खत्म हो गई। जैसे-तैसे कामों को शुरू करके फिर उन्हें आगे के लिए स्थगित करने की आदत एक बीमारी की तरह संसद तक व्याप्त हो गई है, यही शोचनीय विषय है।

बस, एक बात समझ लीजिए। हम जिसे कल कहते हैं, उससे हमारा सामना होने वाला नहीं। वह जब आज बनता है, तभी हम उसका सामना करते हैं। कल नामक समय हमारे अनुभव में साकार होने वाला नहीं है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

'ईशावास्यम् इदम् सर्वम्' के जीवन मूल्य पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव-जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। जब विभिन्न प्राणियों का संवर्धन होगा, तब जैव-विविधता बढ़ेगी और यह धरती एवं मानव जाति खुशहाल होगी।

अनुलोम-विलोम
चिकित्सक दिवस

बुरे हालात में भी निःस्वार्थ सेवा करते डॉक्टर

जब जीवन की डोर किसी अनजानी पीड़ा से उलझने लगती है, सांसें संशय और भय से उखड़ने लगती हैं, तब एक व्यक्ति विश्वास का उजाला बिखेरता है, जो रक्षक भी है और संजीवनी भी, और वह है, नब्ज की भाषा समझने वाला चिकित्सक। 1 जुलाई का दिन भारत में इन्हीं को समर्पित है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमें न केवल उनके योगदान को याद करने का अवसर देता है, बल्कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने और एक संवेदनशील समाज के निर्माण का संकल्प लेने का भी आह्वान करता है।

यह दिवस भारत के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राजनेता डॉ. बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। उनके लिए चिकित्सा केवल पेशा नहीं, बल्कि एक धर्म था- एक ऐसा दायित्व, जो आज भी हर चिकित्सक के हृदय में जीवित है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना किसी युद्ध से कम नहीं। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार, देश में लगभग 13 लाख पंजीकृत चिकित्सक हैं, जिनमें से करीब आठ लाख सक्रिय रूप से सेवा कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार, प्रत्येक 1,000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में यह अनुपात 1:834 है, जो भले ही वैश्विक औसत से बेहतर हो, लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच गहरी खाई इसे कमजोर बनाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 30 प्रतिशत स्वास्थ्य केंद्रों में ही नियमित चिकित्सक कार्यरत हैं।

इन विषम परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय चिकित्सक एक सच्चे योद्धा की तरह हरेक चुनौती का सामना करते हैं। कोविड-19 महामारी इसका सबसे हालिया उदाहरण है। वर्ष 2020 से 2022 के बीच, भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के अनुसार, लगभग 1,600 से अधिक चिकित्सकों ने अपनी जान गंवाई, फिर भी, तमाम डॉक्टर दिन-रात, बिना थके, बिना डरे मरीजों की सेवा करते रहे। उन्होंने न केवल लोगों की जान बचाई, बल्कि भय और अनिश्चितता के बीच रोगियों को मानसिक संबल देते रहे। आज भी भारत में हर दिन औसतन 75 लाख से अधिक लोग चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करते हैं, जिनमें सरकारी अस्पताल, निजी क्लिनिक, स्वास्थ्य शिविर और अब तेजी से बढ़ रही टेलीमेडिसिन सेवाएं भी शामिल हैं। कई चिकित्सक निःशुल्क शिविरों, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सबसे वंचित वर्गों तक पहुंच रहे हैं। हमें उनके योगदान को महत्व देना चाहिए। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या हम अपने डॉक्टरों को वह सब दे रहे हैं, जिनके वे हकदार हैं?

आरके जैन 'अरिजीत', टिप्पणीकार

सेवा भावना से अधिक अब पैसा लुभाने लगा

निस्संदेह, डॉक्टर चाहे आयुर्वेदिक पद्धति के हों, एलोपैथी के या फिर यूनानी पद्धति के जरिये इलाज करने वाले ही क्यों न हों, रोगी की जान बचाने, उन्हें आराम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। यही कारण है कि उनको धरती का भगवान भी कहा जाता है। मगर अफसोस कि कुछ डॉक्टर, रोगी के साथ अपने रिश्ते को दागदार करने से गुरेज नहीं करते।

एक घटना बताता हूं। कुछ वर्ष पहले मेरे एक परिचित को रात में दिल का दौरा पड़ा, उनके साथी उन्हें पास के डॉक्टर के घर यह सोचकर ले गए कि शायद वहां कोई प्राथमिक सहायता मिल सकेगी, लेकिन उस डॉक्टर ने अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोला और अंदर से कहलवा दिया कि इस समय वह मरीजों को नहीं देखते। जाहिर है, उस मरीज को आनन-फानन एक अस्पताल में पहुंचाया गया, जो कुछ दूर था। मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। अगर उस डॉक्टर ने थोड़ी सी इंसानियत दिखाई होती, तो शायद उस मरीज की जान बच जाती। इसी तरह भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मामला है, जिसको रोकने के उपाय करने चाहिए, ताकि कोई भी डॉक्टर किसी की जान की कीमत न लगा पाए।

भारत में आबादी और रोगियों की संख्या तो बढ़ती गई है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में उतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई है। अब इसे डॉक्टरों पर पड़ने वाला दबाव कहें, या उनकी कुछ हद तक अक्षमता कि गलत चिकित्सा की वजह से रोगियों द्वारा दुष्परिणाम झेलने की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। लिहाजा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का औचित्य तभी पूरा होगा, जब सभी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को आदर्श बनाकर उनके मार्ग पर चलेंगे।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत रत्न डॉ बिधान चंद्र राय की जन्म और पुण्यतिथि (दोनों 1 जुलाई) के अवसर पर मनाया जाता है। चिकित्सकों के समाज में योगदान को सम्मान प्रदान करने हेतु मनाए जाने वाले इस दिवस पर चिकित्सकों को अपने दायित्व-बोध का अवलोकन भी अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर प्रगति के बावजूद कई चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। भारत में हालांकि, आजादी के समय जीवन प्रत्याशा लगभग 28 वर्ष थी, जो अब करीब 70 वर्ष है। गत 75 वर्षों में हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, मगर विडंबना यह है कि डॉक्टरों पर रोगियों का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। लिहाजा, इस दिवस के मौके पर सभी चिकित्सक मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को और विस्तृत आयाम देंगे, ऐसी आशा है।

हेमा शर्मा, टिप्पणीकार

चिंतन

उद्योग क्षेत्र की गति पर फोकस बढ़ाना जरूरी

सरकार को उद्योग क्षेत्र पर खास ध्यान देना चाहिए। महीने दर महीने जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में लगातार गिरावट देखी जा रही है। चालू वित्त वर्ष में ही अप्रैल के बाद अब मई में भी आईआईपी में गिरावट दर्ज की गई है। आईआईपी मई में नौ महीने के निचले स्तर 1.2 प्रतिशत पर है। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों ने कमजोर प्रदर्शन किया है। रिजर्व बैंक ने उद्योग क्षेत्र की दिक्कतों को देखते हुए और महंगाई के नियंत्रण में रहने से नीतिगत दर रेपो रेट में तीसरी बार कटौती की है। इसके पीछे एक तर्क यह भी था कि रेपो रेट में कमी होने से उद्योग जगत को सस्ते कर्ज के रूप में लाभ मिलेगा, लेकिन आईआईपी के आंकड़े बा रहे हैं कि कर्ज सस्ते होने के बावजूद उद्योग क्षेत्र की गति सुस्त ही है। आईआईपी के जरिये मापे जाने वाले औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर बीते वर्ष 2024 के मई माह में 6.3 प्रतिशत रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि को भी संशोधित कर 2.6 प्रतिशत कर दिया है, जबकि पहले इसके 2.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। इससे पहले, अगस्त, 2024 में आईआईपी में सबसे कम वृद्धि दर्ज की गयी थी। उस समय वृद्धि दर स्थिर रही थी। वित्त वर्ष 2025-26 में पहले दो माह (अप्रैल-मई) के दौरान औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 5.7 प्रतिशत थी। जून तिमाही के पहले दो महीनों में औद्योगिक उत्पादन में धीमी वृद्धि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में औद्योगिक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जीडीपी में अहम स्थान रखने वाले और रोजगार सृजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले उद्योग क्षेत्र को लंबे समय से नीतिगत स्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। चाहे अगले चरण के आर्थिक सुधार की बात हो या विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौते की बात हो, रुपये का प्रदर्शन हो, प्रगति बहुत धीमी है। जीएसटी, विमुद्रीकरण और कोरोना से टूटे उद्योग क्षेत्र को पीएलआई जैसे प्रोत्साहन स्कीम भर से बूस्ट नहीं मिल रहा है। मेक इन इंडिया अभियान उद्योग क्षेत्र में जान नहीं फूंक पा रहा है। मोबाइल, ऑटो निर्माण क्षेत्र में भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भारत के कोर इंडस्ट्री सेक्टर खनन, बिजली, विनिर्माण (मेनुफैक्चरिंग सेक्टर) उम्मीद के अनुरूप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-मई की अवधि में देश का राजकोषीय घाटा वार्षिक अनुमान का 0.8 प्रतिशत रहा। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का अनुमान है कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडपी) का 4.4 प्रतिशत रहेगा। आंकड़े को देखें तो अनुमान के हिसाब से लक्ष्य नियंत्रित नहीं है। भारत का व्यापार घाटा भी काफी असंतुलित है, जिसमें निर्यात से अधिक आयात है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा गया है कि मूल्य स्थिरता की तरह वित्तीय स्थिरता भी आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी है। दोनों ही स्तर पर भारतीय उद्योग क्षेत्र उथलपुथल का सामना कर रहे हैं। कर सुधार के साथ नए निवेश के लिए प्रोत्साहन माहौल बनाना होगा। बड़े उद्यमियों के साथ लघु व मध्यम उद्यमियों को भी बढ़ावा देना होगा, देश में औद्योगिक विकास की गति का माहौल बनाना होगा, हाल के वर्षों में सरकार बजटरी स्तर पर उद्योग क्षेत्र से डिफोकस हुई है, जिससे औद्योगिक व वित्तीय नियामकीय सुधारों में सुस्ती आई है। उद्योग पर फोकस हो।

डॉक्टरों का सफेद कोट बेदाग रहे

'डॉक्टर्स डे'

डॉ. संजय शुक्ला

डॉक्टर यानि चिकित्सक को 'गॉड ऑफ अर्थ' यानि धरती का भगवान कहा गया है। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देने के पीछे वास्तविकता उसके मरीजों के प्रति करूणा, सहानुभूति, संवेदनशीलता, परोपकार, बीमार को निरोग तथा मौत के मुंह में गए व्यक्ति की ज्ञान, कौशल और दक्षता से उसकी जीवनरक्षा करने की ईश्वरीय क्षमता है। व्यवसायिक नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन के वर्तमान दौर में आज डॉक्टरी पेशा ही एक ऐसा पेशा है जिसकी सर्वोच्च सामाजिक प्रतिष्ठा है। भारत में पौराणिक काल से लेकर आधुनिक दौर में वैद्यों, हकीमों और डॉक्टरों का व्यवसायिक नजरिए से सम्मानजनक स्थान रहा है। देश के महान चिकित्सक डॉ. बिधानचंद्र राय जिनका जन्मदिन 1 जुलाई है की स्मृति में भारत में प्रतिवर्ष 'डॉक्टर्स डे' मनाया जाता है। डॉ. राय की ख्याति केवल उच्च शिक्षा प्राप्त मेडिकल टीचर और डॉक्टर के तौर पर ही नहीं थी बल्कि उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बतौर सेनानी असहयोग आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था।

डॉ. बिधानचंद्र राय आगे चलकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने तथा उन्हें देश के सर्वोच्च अलंकरण 'भारत रत्न' से नवाजा गया। गौरतलब है कि दुनिया का पहला डॉक्टर्स डे 30 मार्च 1933 में जॉर्जिया में मनाया गया अनेक देशों में यह दिवस अलग-अलग तिथियों में मनाया जाता है। दरअसल दुनिया भर में डॉक्टर्स डे मनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य चिकित्सकों के प्रति नागरिकों द्वारा सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापन है। इसके इतर स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण और लचर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के चलते चिकित्सा जैसा पवित्र पेशा अब अनेक विसंगतियों से जूझने लगा है। बाजारवाद और कार्पोरेट घरानों के भारी निवेश के चलते चिकित्सा का क्षेत्र सेवा की जगह कमाई का जरिया बन रहा है फलस्वरूप डॉक्टरों के सफेद कोट यानि एप्रन पर दाग के छींटें पड़ने लगे हैं जो चिंताजनक है। गौरतलब है कि भारत जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश में स्वास्थ्य का क्षेत्र शहरी और ग्रामीण तथा अमीर व गरीब के बीच में बंटा हुआ है। खस्ताहाल सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच देश की दो तिहाई आबादी आज भी सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है जहां डॉक्टरों सहित अन्य संसाधनों की भारी कमी है। दूसरी ओर पांच सितारा अस्पताल हैं जहां डॉक्टर कार्पोरेट घरानों के मुलाजिम हैं लेकिन इन अस्पतालों में किसी भी प्रकार के व्यवस्थागत चूक का ठीकरा इन्हीं डॉक्टरों पर फूटता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जारी असमानताओं और विसंगतियों के कारण अब डॉक्टर और मरीज के बीच भरोसे का डोर लगातार कमजोर हो रहा है फलस्वरूप चिकित्सक और मरीज के परिजनों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें आम हो चुकी है। हालांकि सभ्य समाज में ऐसे संघर्ष को कदापि स्वीकार नहीं किया जा लिहाजा आज जरूरत डॉक्टर और मरीज के बीच बढ़ रहे अविश्वास को खत्म करने की जरूरत है इसके लिए समाज और चिकित्सक बिरादरी के बीच संवाद के फासले को कम करना होगा। एक दौर वह भी था जब चिकित्सा और शिक्षा को केवल सेवा का क्षेत्र माना जाता था लेकिन वर्तमान परिवेश में इन दोनों क्षेत्रों ने कॉर्पोरेट यानि व्यवसाय का शक्ल अख्तियार कर लिया है फलस्वरूप समाज और मरीजों के नजर में डॉक्टर की छवि व्यापारी अथवा 'लुटेरे' की बनने लगी जो उचित नहीं है क्योंकि इन संस्थानों में डॉक्टर सिर्फ एक पेशेवर व्यक्ति है जबकि प्रबंधन से उसे कुछ लेना-देना नहीं है। हालांकि छोटे नर्सिंग होम जिनका संचालन खुद डॉक्टर करते हैं वहां के बारे में कई बार मरीजों से अनाप-शनाप फीस लेने और स्मार्ट कार्ड घोटाले की खबरें सामने आई है लिहाजा चिकित्सक बिरादरी को इस दिशा में आत्ममंथन की भी जरूरत है।

विडंबना है कि नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन के वर्तमान दौर में चिकित्सा जैसा मुकद्दस पेशा भी इससे अछूता नहीं है। बीते कुछ सालों में निजी अस्पतालों के डॉक्टरों द्वारा अनावश्यक गर्भाशय निकालने, गैरजरूरी सर्जरी करने, धोखेबाजी करके किडनी निकालने, हृदय के धमनियों की सर्जरी के दौरान लगने वाले "स्टेंट" अथवा एंजियोप्लास्टी में घपला करने, लिंग परीक्षण अथवा एबॉर्शन में पैसे ऐंठने, स्मार्ट कार्ड घोटाले में संलिप्तता और पैसों के भुगतान के आड़ में शव को बंधक बनाने जैसी खबरें सामने आई है। आज आमधारणा यह बनती जा रही है डॉक्टर अपने कमीशन और अस्पतालों के भारी-भरकम खर्च जुटाने के लिए मरीजों की गैर जरूरी जांच कराते हैं अथवा भर्ती रखते हैं। इसी प्रकार यह भी धारणा है कि डॉक्टर दवा कंपनियों से मिलने वाले उपहार या सैर-सपाटे के ऐवज में मरीजों को सस्ती दवाओं की जगह महंगे ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं।हालांकि चिकित्सकों से संबंधित उपरोक्त खबरें और धारणाओं में अर्धसत्य है क्योंकि आज भी अधिकांश चिकित्सक अपने पेशे और

प्रतिष्ठा के प्रति संजीदा हैं। महज चंद डॉक्टरों के अनैतिक गतिविधियों के चलते समूचे चिकित्सक समुदाय को कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अपने मरीजों के सेहत और जिंदगी के प्रति कितना फिक्रमंद हैं? इसका उदाहरण हमने बीते वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देखा जब पूरी दुनिया अपने घरों में तालेबंद थी तब यही चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ दिन-रात हजारों मरीजों की सांसों की डोर थामने अपनी जान को दांव पर लगा रहे थे। इस महामारी से संक्रमितों के उपचार के दौरान जहां देश के हजारों डॉक्टर और सहकर्मी कोरोना से संक्रमित हुए वहीं लगभग 1000 डॉक्टरों की मौत इस महामारी से हुई। हमें यह भी याद रखना होगा कि उस त्रासदी के दौर में समाज का एक वर्ग जहां डॉक्टरों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहा था वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उन थूक रहे थे या फिर पत्थर और गाली बरसा रहे थे। दरअसल डॉक्टर की जिंदगी में ऐसे क्षण बार - बार आते हैं जब कोई मरीज जिंदगी के लिए निर्णायक संघर्ष करते रहता है तब यह संघर्ष अकेले मरीज का ही नहीं होता है बल्कि इस संघर्ष का अहम हिस्सा उस डॉक्टर का होता है जो मरीज की जिंदगी के लिए खुद जद्दोजहद कर रहा होता है। बीमार को बीमारी और मौत के मुंह से लौटाकर उसे सेहतमंद बनाने और जिंदगी बचाने के असली मायने एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। सच्चाई यह है कि हर डॉक्टर मरीज की जान बचाने और उसे तंदुरुस्त रखने की हरसंभव कोशिश करता है ऐसे में यदि किसी मरीज के साथ अनहोनी हो जाए तो चिकित्सक को दोषी ठहराना कतई उचित नहीं है। लेकिन अपवाद स्वरूप सच्चाई यह भी है कि कुछ मामलों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही और उदासीनता भी सामने आई है जिसके चलते मरीजों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। अलबत्ता चिकित्सक संगठनों की भी जवाबदेही है कि वह चिकित्सा पेशे की धूमिल होती साख के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि इस पेशे की पहचान सफेद कोट दागदार होने से बचे। विचारणीय है कि आखिरकार काम के दबाव और असुरक्षा के बीच डॉक्टर कैसे काम करते होंगे? अहम मसला यह भी कि जिसके जिम्मे लोगों के जान की सलामती है उसके खुद के जान- माल की सुरक्षा के लिए सरकार या प्रशासन के पास अब तक कोई भी प्रभावी कानून या सुरक्षा के प्रबंध नहीं है।

बहरहाल डॉक्टरी पेशे की धूमिल होती छवि और इस पेशे पर उठ रही उंगलियों के मद्देनजर यह भी विचारणीय है कि आखिरकार डॉक्टर भी समाज का ही हिस्सा है तथा उसकी भी पारिवारिक जिम्मेदारी और जरूरतें हैं लिहाजा नैतिकता और परोपकार की अपेक्षा इसी बिरादरी से क्यों? आखिरकार वर्तमान भौतिकवादी दौर में डॉक्टरों को भी पैसों की जरूरत है लेकिन इन पैसों की कमाई के तरीकों पर जरूर बहस होना चाहिए क्योंकि यह सीधे तौर पर व्यक्ति के सेहत से जुड़ा मसला है। यदि कोई चिकित्सक अपनी योग्यता और कौशल के बल पर इस पेशे की शुचिता और शपथ के मर्यादा में पैसा कमाता है तो यह कतई अनैतिक नहीं है। इसके उलट यदि कोई चिकित्सक अपने पेशे को ऐनकेन प्रकारेण कमाई का जरिया तथा मरीज को एक ग्राहक समझे तो यह चिकित्सा के बुनियादी उसूलों के सर्वथा विपरीत है।अलबत्ता डॉक्टरों की नयी पीढ़ी की जवाबदेही है कि वे 'व्हाइट कोट सेरेमनी' में लेने वाले शपथ के प्रति प्रतिबद्ध हों आखिरकार उनका यह कोट करूणा, परोपकार,स्वच्छता, व्यावसायिकता और विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। बहरहाल 'डॉक्टर्स-डे' की सार्थकता तब है जब चिकित्सक अपनी सामाजिक और व्यवसायिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील हो ताकि इस पेशे की शुचिता और सम्मान की रक्षा संभव हो सके। समाज से भी अपेक्षा है कि वह चिकित्सकों के प्रति संवेदनशील बनें आखिरकार ईश्वर भले ही हमें जीवन देता है लेकिन गंभीर बीमारियों और दुर्घटनाओं के दौरान जीवन की रक्षा तो डॉक्टर ही करता है।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस

मुनीष भाटिया

सेवा और गुणवत्ता से सशक्त हो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था

हर वर्ष एक जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के रूप में चुना गया है। डॉ. रॉय ने चिकित्सा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया, जो न केवल पेशेवर उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि देश सेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति उनके समर्पण को भी दर्शाता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची सेवा सीमाओं और पेशेवर सीमाओं से परे होती है। यह विशेष दिन केवल एक औपचारिक स्मरण नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत डॉक्टरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का अवसर है, जो दिन-रात बिना थके मानव सेवा में रत रहते हैं। किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की सफलता में यदि कोई सबसे स्थायी और संवेदनशील स्तंभ है, तो वह डॉक्टर ही हैं। आज के दौर में जब चिकित्सा के क्षेत्र में युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, तो यह दर्शाता है कि करियर के साथ-साथ सेवा भाव भी उनमें कितना गहरा है। नीट जैसी कठिनतम परीक्षाओं में लाखों की तादाद में अभ्यर्थियों का भाग लेना इसी का सूचक है। यह रुझान एक सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है, जहां युवा सिर्फ आर्थिक लाभ के बजाय मानवता की सेवा को भी महत्व दे रहे हैं। इसके अलावा, मेडिकल के क्षेत्र में भी कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु उनमें प्रवेश ले रहे अभ्यर्थियों की गुणवत्ता पर ध्यान देना आज बेहद जरूरी हो चला है। मेडिकल संस्थानों को केवल मुनाफ़ा कमाने के उद्देश्य से लाखों-करोड़ों की फीस लेने पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि एक उज्ज्वल भविष्य के साथ गरीब का बच्चा भी चिकित्सक बनने के अपने सपने को पूरा कर सके। यह सुनिश्चित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि चिकित्सा शिक्षा सभी वर्गों के लिए सुलभ हो। साथ ही, चिकित्सा संस्थानों पर भी कड़ी निगरानी जरूरी है कि कहीं वे केवल मुनाफ़ा बनाने के उद्देश्य में ही तो नहीं लगे हैं, कहीं उनके द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में समझौता तो नहीं हो रहा। दुर्भाग्य से, नीट परीक्षा में धांधलेबाजी की खबरें चिंताजनक हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीकों से चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश पा जाता है, तो यह सोचने का विषय है कि ऐसे भावी चिकित्सक किस तरह का सेवाभाव रखेंगे। भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रवेश पाने वाले व्यक्तियों में इन मूलभूत गुणों की कमी होने की आशंका रहती है, जो अंततः रोगी की देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। भ्रष्ट आचरण पर कठोर निगरानी और त्वरित कार्रवाई की सख्त आवश्यकता है। चिकित्सा शिक्षा की नींव को कमजोर करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कड़े नियम, पारदर्शी प्रक्रियाएं और सख्त दंड प्रणाली लागू करके ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में केवल योग्य और सेवा-भाव से प्रेरित व्यक्ति ही प्रवेश पाएं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नैतिक मूल्यों और पेशेवर मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तभी चिकित्सक दिवस की सही मायनों में सार्थकता सिद्ध हो सकती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नैतिक मूल्यों और पेशेवर मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। तभी चिकित्सक दिवस की सही मायनों में सार्थकता सिद्ध हो सकती है। चिकित्सक केवल एक पेशेवर नहीं होता, वह कई रूपों में सेवा करता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या हम डॉक्टरों को वह सम्मान और सुविधाएं दे रहे हैं, जिसकी वे अधिकारी हैं? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सेवा भावना का शोषण न हो, बल्कि उसे सम्मान और सहयोग मिले। चिकित्सा केवल एक करियर विकल्प नहीं है, यह एक जीवन-दर्शन है। यह उन लोगों का मार्ग है जो जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने का माध्यम मानते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सेवा, सहानुभूति और समर्पण से परिपूर्ण है। चिकित्सकों को भी यह याद रखना होगा कि उनका पेशा एक महान सेवा है। उन्हें मरीज के साथ अपने व्यवहार में 'अपनत्व' और संवेदनशीलता को कायम रखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से चिकित्सकों के दुर्व्यवहार की खबरें, जिसमें परिजनों द्वारा 'गलत इलाज' के नाम पर आरोप लगाए गए हैं, चिंता का विषय हैं। चिकित्सकों को यह समझना होगा कि उपचार की सफलता में वैज्ञानिक कौशल के साथ मानवीय स्पर्श और सहानुभूति का भी उतना ही महत्व है। एक विनम्र और संवेदनशील व्यवहार मरीज के डर को कम करता है और उसके ठीक होने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। पारदर्शिता, स्पष्ट संवाद और रोगियों के प्रति सम्मान एक स्वस्थ चिकित्सा संबंध की नींव है।

बड़े भाग मानुष तनु पावा

संकलित

दर्शन

संवाद का ऐसा सांगोपांग निर्वहन संसार के किसी स्मृति साहित्य में नहीं मिलेगा, जो श्रीरामचरितमानस में है। पूरा मानस भक्त काकभुशुंडि और ज्ञानी पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद है। भक्त काकभुशुंडि वक्ता हैं और ज्ञानी गरुड़ श्रोता हैं। भक्त प्रतिपादन कर रहा है और ज्ञानी जिज्ञासा कर रहा है। भक्त के प्रतिपादन में भावना का वह समुद्र लहराता है, जिसमें तनिक भी खारापन नहीं होता है और ज्ञानी की जिज्ञासा में कुतर्क का अभाव होता है। भक्त और ज्ञानी दोनों का परम उद्देश्य रामराज्य है, जो आचरण के उपादान के बगैर संभव नहीं है। समग्र रामकथा श्रवण के पश्चात पक्षीराज गरुण काकभुशुंडि जी से सात प्रश्नों की जिज्ञासा करते हैं। पहला प्रश्न पूछते हुए वह कहते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? काकभुशुंडि जी उत्तर देते हैं कि मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है, क्योंकि मैंने स्वयं भी इसी शरीर के रहते भगवान और उनकी भक्ति को पाया है। वह कहते हैं कि मनुष्य तन ही वह उपलब्धि है, जो मोक्ष सुख का अनुभव भी करा सकता है। स्वर्ग के सुख को लोग भले ही श्रेष्ठ मानते हों, पर अंत में वह भी अल्प है और दुख का कारण बनता है। भक्त के जीवन में जो प्राप्त शरीर है, वह भी आराध्य को पाने का उपादान होने के कारण पूज्य हो जाता है। संसार में भी किसी व्यक्ति के सहयोग से यदि हमें कुछ विशेष उपलब्धि हो गई हो तो हम जीवन भर उसके कृतज्ञ रहते हैं, उसी प्रकार काकभुशुंडि जी कह रहे हैं कि शरीर मिथ्या तो तब होगा, जब इसका उद्देश्य भोगों की प्राप्ति हो।

एक दिन का पुण्य ही क्यूँ

संकलित

प्रेरणा

निर्जला एकादशी से अगले दिन एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने पहुंचा। सज्जन व्यक्ति ने 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया। भिखारी को प्यास भी लगी थी, वो बोला बाबूजी एक गिलास पानी भी पिलवा दो, गला सूखा जा रहा है। सज्जन व्यक्ति ने गुस्से में कहाः तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम यहां, पहले पैसे, अब पानी, थोड़ी देर में रोटी मांगेगा, चल भाग यहाँ से। भिखारी बोलाः बाबूजी गुस्सा मत कीजिये मैं आगे कहीं पानी पी लूंगा। पर जहां तक मुझे याद है, कल आपने निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ किया था, तथा कल इसी दुकान के बाहर मीठे पानी की छबील लगी थी और आप स्वयं लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे, मुझे भी कल आपके हाथों से दो गिलास शर्बत पीने को मिला था। मैंने तो यही सोचा था, आप बड़े धर्मात्मा आदमी है, पर आज मेरा भरम टूट गया। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिये लगाई होगी? मुझे आज आपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे छमा करना अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूँ तो। सज्जन व्यक्ति को बात दिल पर लगी, उसकी नजरों के सामने बीते दिन का प्रत्येक दृश्य घूम गया। उसे अपनी गलती का अहसास हो रहा था। वह स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर उस बाबा को देते हुए उसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। भिखारीः बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नही, परन्तु अगर मानवता को अपने मन की गहराइयों में नही बसा सकते तो एक-दो दिन किये हुए पुण्य कार्य व्यर्थ ही हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

बेईमानी का धन

आज भौतिकवादी और आधुनिक युग में कुछ लोगों को धन की इतनी भूख बढ़ रही है कि वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि, धन एक वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है, और इसका विपरीत है अधर्म का खजाना। लेकिन आज बहुत से लोग अमीर बनने के चक्कर में बेईमानी, हेराफेरी, अनैतिकता की राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि गलत तरीकों से कमाई धन-दौलत ज्यादा दिन सुख नहीं दे सकती। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। अगर हम बेईमानी कि कमाई से अन्न खरीद कर खाएंगे या अपने परिवार को खिलाएंगे तो क्या वो अन्न हमारे या हमारे परिवार के लिए उचित भोजन होगा? - विवेक शर्मा, दुर्ग

करंट अफेयर

चीन ने जापान के सीफुड से आयात प्रतिबंध हटाया

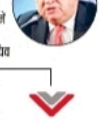

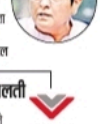

बीजिंग। चीन ने सुनामी से नष्ट हुए फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से थोड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल छोड़े जाने को लेकर लगभग दो साल के प्रतिबंध के बाद जापान से सीफूड के आयात पर प्रतिबंध हटा लिया है। सीमा शुल्क एजेंसी की ओर से जारी एक नोटिस में कहा गया है कि रविवार को प्रतिबंध हटा लिया गया है और जापान के अधिकतर हिस्सों से आयात फिर से शुरू हो जाएगा। अगस्त 2023 में लगाया गया यह प्रतिबंध जापान के मत्स्य उद्योग के लिए बड़ा झटका था। जापानी सीफूड के लिए सबसे बड़ा विदेशी बाजार चीन का है। जापान अपने सीफूड का 20 फीसदी से अधिक हिस्सा चीन को निर्यात करता है। फुकुशिमा स्थित परमाणु संयंत्र 2011 में एक भूकंप के बाद आई भीषण सुनामी से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कई वर्षों की बहस के बाद, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कंपनी को सरकार से यह अनुमति मिल गई कि वह इस अपशिष्ट जल को समुद्र में धीरे-धीरे छोड़े, बशर्ते कि पहले इसे शोधित कर लिया जाए ताकि अधिकतर रेडियोधर्मी तत्वों को हटा दिया जाए। चीन ने इससे असहमति जतायी थी और यह कहते हुए सीफूड के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था कि रेडियोधर्मी जल को समुद्र में छोड़े जाने से मत्स्य उद्योग और तटीय समुदाय खतरे में आ जाएगा।

ऑफ बीट

शहरों की वजह से बढ़ रहा धरती का तापमान

जलवायु परिवर्तन से निपटने में शहरों की केंद्रीय भूमिका होती है। वे 67 से 72 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कर रहे हैं जो पृथ्वी को गर्म कर रही हैं। साथ ही, शहरों में 'ग्लोबल वार्मिंग' (वैश्विक तापमान वृद्धि) का खतरा भी बढ़ रहा है। बाढ़, आग और सूखा स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर डालकर घरों और व्यवसायों की बीमा की लागत से लेकर सब कुछ प्रभावित कर रहे हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां 90 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। पूरी दुनिया में शहरों में चार अरब से अधिक लोग रहते हैं। हमारा नया अध्ययन शहरों के निर्माण और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए 16 प्राथमिकता वाली कार्रवाइयों को चिह्नित करता है। हमारे शहरों को डिजाइन, उनका निर्माण और प्रबंधन करते समय जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख विचार होना चाहिए। उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन को कम से कम किया जाना चाहिए और अंततः समाप्त किया जाना चाहिए। हमें ऐसे स्थानों पर और ऐसे तरीकों से निर्माण करना चाहिए, जो जलवायु जोखिम को कम करें। लेकिन हमारे शहरों के निर्माण पर नियंत्रण वाली नीतियां इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाती हैं। तीन स्थानीय सरकारी क्षेत्रों के एक हालिया अध्ययन में अनुकूलन और शमन पर केवल सीमित कार्रवाई होने का पता चला है।

ट्रेंड

युवाओं को लाभ होगा

मेरा भारत 2.0!। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम राष्ट्र निर्माण को गति देने के लिए युवा शक्ति को डिजिटल उपकरणों से लैस कर रहे हैं। इस परिवर्तनकारी उन्नयन से मेरे भारत मंच पर पंजीकृत 1.76 करोड़ से अधिक युवाओं को लाभ होगा।

-मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री

भविष्य में निवेश

मैंने स्पेन में विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथे सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन दान के बारे में नहीं है। यह सम्मान के जीवन को बदल करने के बारे में है। यह उस भविष्य में निवेश करने के बारे में है जिसे हम मिलकर बनाना चाहते हैं।

-एंटोनियो गुतारेस, यूएन महासचिव

पहले मूल्यों को सीखें

बहुत अच्छा। अगर हम व्यापार से पहले मूल्यों को सीखें। अगर भगवान से पहले माता-पिता के प्रति कृतज्ञ होना सीखें। जीवन खुशहाल होगा। यदि हम शिक्षा से पहले संस्कार, भगवान से पहले माता-पिता को जान लें तो जीवन सरल हो जाएगा।

-किरण बेदी, पूर्व उप राज्यपाल

आपा खोने से मदद नहीं मिलती

काम पर बिताए अपने सभी सालों में, मैंने कभी किसी पर चिल्लाया नहीं और मुझे इस बात पर गर्व है। बेशक, मेरे पास क्रोध, निराशा और हताशा के क्षण भी आए हैं। लेकिन मैंने सीखा है कि अपना आपा खोने से कोई मदद नहीं मिलती।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।